प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

# माही की गूंज

बेबाकी के साथ..सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com


**सुविचार**



कुछ समस्याओं से परेशान मत हों क्योंकि जीवन एक सड़क की तरह है और समस्याएं गति तोड़ने वालों की तरह है। यह हमें बड़ी दुर्घटना से बचाएगी।

बीके शिवानी


वर्ष-02, अंक - 50 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 17 सितम्बर 2020 पृष्ठ-8, मूल्य-5 रुपए


## कोविड-19 के चलते 5 दिन के लिए एमपी हाईकोर्ट बंद

**जबलपुर, एजेंसी।** प्रदेश और जिले में बढ़ रहे कोरोना के मामले एवं राज्य अधिवक्ता परिसद में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट को 5 दिनों के लिए बंद किया गया है। इस दौरान पूरी तरह से हाईकोर्ट में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और वीसी से भी सुनवाई नही होगी। इस आशय का आदेश चीफजस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी ने जारी किया है। इस दौरान हाईकोर्ट परिसर को सेनेटाइज किया जाएगा। इस आदेश के बाद अब हाईकोर्ट 21 सितंबर को खुलेगी।

## एलएसी पर तनाव, 20 दिनों में तीन बार हुई फायरिंग, लद्दाख में भारत ने बढाई सेना



**नई दिल्ली, एजेंसी।** वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीमा से सटे इलाकों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हर हरकत पर नजर भारतीय सेना बनाए हुए है। बीते 20 दिनों में भारत और चीन के बीच उत्तरी पैंगोंग झील के समीप फायरिंग की कम से कम तीन घटनाएं हो चुकी हैं। 45 साल में यह पहली बार है जब एलएसी पर फायरिंग की कोई घटना हुई हो। सेना के सूत्रों ने कहा कि, पहली घटना तब हुई जब भारतीय सेना ने 29-31 अगस्त के बीच दक्षिणी बैंक पंगोंग झील के पास ऊंचाइयों पर कब्जा करने की चीनी कोशिश को नाकाम कर दिया, जबकि दूसरी घटना 7 सितंबर को मुखपारी के पास हुई। सेना के सूत्रों ने कहा कि, तीसरी घटना 8 सितंबर को पैंगोंग झील के उत्तरी तट के पास हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों के सैनिकों ने 100 से अधिक राउंड हवाई फायरिंग की थी, इस दौरान चीनी सेना आक्रामक तरीके से बर्ताव कर रही थी। यह घटना ऐसे समय में हुई थी जब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में थे, जहां सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए चीनी समकक्ष से उन्होंने मुलाकात की थी। बातचीत के दौरान दोनों पक्ष कोर कमांडर-स्तरीय वार्ता करने वाले थे, लेकिन अभी तक चीनी पक्ष की ओर से तारीख और समय की पुष्टि नहीं की गई है।

**जिले से काम नही बना तो इंदौर से जुगाड़ बिठा कर करवा ली रिश्तेदारो की फर्जी नियुक्ति**

# तत्कालीन सहायक आयुक्त गणेश भाबर ने इंदौर पहुंचकर भी नहीं छोड़ा बाबू अटकान का साथ

## एक ही अधिकारी के पद के साथ बदले नियुक्ति आदेश में हस्ताक्षर आखिर कैसे ?

**माही की गूंज झाबुआ। संजय भेटवरा**

जिले में जुगाड़ कर अपने कई रिश्तेदारो की नोकरी लगवाने के बाद अपने ओर भी रिश्तेदारों की नोकरी के लिए बाबू रामचंद अटकान आदिवासी विकास विभाग में लगातार सक्रिय रहा। एक के बाद एक हुई बाबू के रिश्तेदारो की भर्ती वही दुसरी और शिकायतकर्ता रमेश धानक की ओर से लगातार भर्तीयो पर खड़े किए गए सवालों और शिकायत के बाद बाबू के दूसरे रिश्तेदारों की भर्ती पर कुछ समय के लिए विराम लग गया, लेकिन बाबू अटकान किसी भी तरह से अपने बाकी और परिवार के सदस्यों के लिए सतत् जुगाड़ में लगा ही रहा।



कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश 9 मई 2017 क्रमांक/स्था.3-2/2445/2017/10866 जिसके विरुद्ध जाकर संभाग उपायुक्त ने कर दी नियुक्ति।

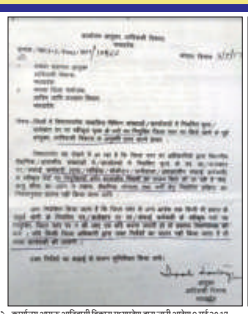



गणेश भाभर के झाबुआ सहायक आयुक्त होकर जारी आदेश जिसमे हस्ताक्षर और संभाग उपायुक्त इंदौर के पद पर रहकर जारी हस्ताक्षर अलग-अलग है।

संभाग उपायुक्त इंदौर द्वारा नियम के विरुद्ध की गई बाबू की बेटी और रिश्तेदार की नियुक्ति का आदेश, जिसमे नियुक्ति पद तक का उल्लेख नही किया गया हैं।

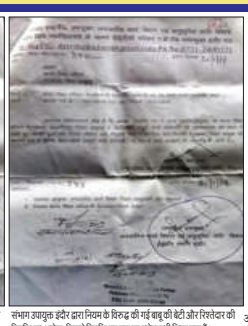

झाबुआ से सहायक आयुक्त गणेश भाभर के तबादले के बाद झाबुआ से नई नियुक्ति के लिए झाबुआ से काम नही जमने के बाद इस बार इंदौर का रुख किया, जहा संभाग उपायुक्त के माध्यम से अगली नियुक्ति, नियम के विरुद्ध करवाई गई। मामले की बारीकी से जाच की गई तो पता लगा कि, इंदौर में संभाग उपायुक्त के पद पर वही है जो पूर्व में झाबुआ में सहायक आयुक्त रह चुके गणेश भाभर ही पदस्थ थे, जिन्होंने अपने ही विभाग के उच्च अधिकारी के आदेश की अवेहलना कर बाबू के करीबी रिश्तेदारों की झाबुआ में नियुक्ति की थी, इस बार बाबू का झाबुआ से नही जमा तो अपने दो और करीबी रिश्तेदारों के आदेश एक बार फिर उच्च अधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए संभाग उपायुक्त गणेश भाभर से करवा ली, नियुक्ति पर यू ही सवाल खड़े नही हो रहे आखिर अब तक झाबुआ से हो रही अवैध और फर्जी नियुक्ति अचानक झाबुआ से इंदौर से क्यो हुई ? क्या दोनों पदों पर एक ही अधिकार का होना महज एक इतेफाक हैं या फिर पैसो की लेंन-देंन के आगे सब कुछ नियम विरुद्ध जाकर जानबूझ कर किया गया कार्य है ? सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि, एक ही अधिकारी ने एक ही विभाग के अलग-अलग पदों पर रहते हुए नोकरी के लिए जारी आदेश में अलग-अलग हस्ताक्षर क्यो किए ?

### संभाग स्तर की मिलीभगत से हुई और भी नियुक्ति

जैसे-जैसे बाबू अटकान के रिश्तेदार आदिवासी विकास विभाग का हिस्सा बनते जा रहे हैं, वैसे-वैसे विभाग के कई कर्मचारियों और अधिकारियों की आखों की किरकिरी अटकान बनता जा रहा था। शिकायतकर्ता धानक द्वारा की गई फर्जी भर्तियों की शिकायतो पर चल रही जांच के कारण जिले के अधिकारियों ने हाथ ढीले कर दिए, पर कहते हैं पैसा बोलता है बस बाबू ने अगली सेटिंग सीधे सम्भाग से बिठा कर बाबू ने उसकी एक ओर पुत्री पूजा पति दिनेश चौहान और बहन के दामाद सुरेश पिता गिरधारी मार की नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के रूप में संभागीय उपायुक्त इंदौर द्वारा क्रमांक/ शिका.स्था./2019/372 इंदौर दिनांक 21 जनवरी 2019 से कन्या शिक्षा परिसर पेटलावद में कर दी गई, आदेश में ये तक नही दर्शाया गया कि, दोनों की नियुक्ति किस पद पर की गई, का कोई उल्लेख आदेश में नही किया गया। आदेश में प्राचार्य के जिस पत्र का संदर्भ में हवाला दिया उसकी दिनांक 20 जनवरी 2019 बताई गई, मतलब पेटलावद से इंदौर तक कि विभागीय पत्रों की आवक-जावक मात्र एक दिन में पूरी कर ली गई आखिर कैसे ? का सवाल ही स्वयं ही फर्जी और अवैध नियुक्ति की पुष्टि करता हैं। जबकि कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश द्वारा एक आदेश दिनांक 9 मई 2017 को जारी आदेश क्रमांक/ स्था.3-2/ 2445/ 2017/ 10866 के अनुसार संभागीय उपायुक्त के अधिकार क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति करना वर्जीत है।

### एक ही अधिकारी के पद के साथ आखिर कैस बदले हस्ताक्षर ? भर्ती के नाम पर हुआ बड़ा खेल

प्रमोशन के साथ एक ही अधिकारी के दो अलग-अलग पद पर रहते हुए बाबू के परिवार के सदस्यों की भर्ती के किये गए आदेशो की जाँच की गई तो, एक चोकाने वाला तथ्य ऐसा भी सामने आया कि, एक ही अधिकारी द्वारा जारी किए गए नियुक्ति आदेश में हस्ताक्षर अलग-अलग किये गए है। मामले की जानकारी जुटाई गई तो पता लगा कि, दोनों हस्ताक्षर एक अधिकारी के थे, लेकिन एक हस्ताक्षर शार्ट में किए गए, जबकि दूसरे हस्ताक्षर में पूरे हस्ताक्षर थे, मामले की और गहराई में जाने पर पता लगा कि, अधिकारी विभागीय डाक ओर शिकायत या आवेंदन पत्र आदि की रिसिप्ट पर शार्ट में हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन विभागीय आदेश या नियुक्ति आदेश या विभागीय जरूरी दस्तावेजो पर अधिकारी को अपने अधिकृत हस्ताक्षर करना होते है, लेकिन गणेश भाभर ने झाबुआ सहायक आयुक्त रहते बाबू के परिवार के नियुक्ति आदेश जो कि, विभागीय महत्त्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है, उस पर शार्ट में हस्ताक्षर किए हैं जो कि, अवैध भी मान्य हो सकते हैं, जबकि संभाग उपायुक्त के पद पर रहते हुए गणेश भाभर ने बाबू अटकान के ही अन्य रिश्तेदार के लिए जारी आदेश में पूर्ण हस्ताक्षर किए हैं। यदि बारीकी और सिलसिलेवार रूप से बाबू अटकान के परिवार के सदस्यों की फर्जी और अवैध रूप से हुई भर्तियों का खुलासा नही होता तो, शायद ही अधिकारियों की मिलीभगत ओर पद के दुरुपयोग का सत्य सामने नही आता, हो सकता हैं शिकायतो की जांच में भी ये तथ्य जाँचकर्ता के सामने आए होंगे लेकिन मामले को अधिकारियों की शह ओर इशारों पर दबा दिया गया हो।

## नए संसद भवन के लिए दो कंपनियां आई आगे

**नई दिल्ली, एजेंसी।** नए संसद भवन के निर्माण के लिए टेक्निकल राउंड में क्वालिफाई करने के बाद मुंबई की दो कंपनियां-लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड और टाटा प्रोजेक्ट्स ने बुधवार को वित्तीय बोलियां जमा कराई हैं। कुल तीन कंपनियों ने टेक्निकल राउंड क्वालिफाई किया था, लेकिन सिर्फ दो ने ही फर्म्स फाइनेंशियल बिड्स जमा कराए। कंपनियों को बुधवार तक फाइनेंशियल बिड्स जमा कराने थे। एक सरकारी आधिकारिक सूत्र ने बताया, पहले राउंड में सिर्फ तीन कंपनियों ने प्री-क्वालिफाई किया था और सिर्फदो ने ही बिड्स जमा कराए। नए संसद भवन के लिए दोनों कंपनियों में से, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861 करोड 90 लाख और लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड ने 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई है।

## यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के 12 राज्यों में आईएसआईएस सबसे अधिक सक्रिय

**नई दिल्ली, ऐजेन्सी।** दुनियाभर में आतंक का साया तेजी से बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए दुनियाभर के नेता एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी आतंक के साये से बच नहीं पाता है। आतंकवाद के मसले पर भारत कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। आतंकवाद के मसले पर आज राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह मंत्रालय ने जवाब दिया। गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने राज्य में इस बात की जानकारी दी कि, देश में 12 ऐसे राज्य हैं, जहां आईएसआईएस के आतंकी सबसे अधिक सक्रिय हैं। इनमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य भी शामिल हैं।

# दूसरी महिला से संबंध बनाने के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर बच्चों सहित निकाला घर से

## महिला ने की शिकायत दर्ज कराते हुए पति, ससुर, जेठ सहित दूसरी महिला पर मारपीट कर घर से निकालने का लगाया आरोप

**माही की गूंज बामनिया, गौरव भंडारी।**

महिला प्रताड़ना को लेकर सरकार ने लाख कदम उठाए हो लेकिन आदिवासी बाहुल्य जिले में महिलाएं आज भी घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के शिकार हो रही हैं, खास कर ग्रामीण क्षेत्र में एक पत्नी के होते दूसरी पत्नी लाने की परम्परा आज भी जारी है, जिससे महिलाओं को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है और मासूम बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो रहा है। बामनिया के कालजिया फलिये की महिला भुंडी पति सोनू गरवाल को उसके पति सोनू गरवाल निवासी रुनजी ने दो मासूम बेटियों सहित मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और कारण वही दूसरी महिला को घर लाना।

प्रताड़ित महिला ने करवड़ चौकी पर आवेदन देकर पति, ससुर, जेठ सहित दूसरी महिला पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। पीड़ित भुंडी पति सोनु गरवाल निवासी रुणजी ने बताया कि, उसका पति सोनु पिता लक्ष्मण गरवाल, जेठ प्रकाश पिता मोहन गरवाल, ससुर लक्ष्मण और पति की दूसरी पत्नी



पीड़ित भुंडी और उसकी दो मासूम बेटिया जिसे सुसराल वालो ने मारपीट कर निकाल दिया।

माना पिता रमेश भुरिया निवासी पोलारूण्डा ने मारपीट कर मासुम लड़कियो के साथ घर से निकाल दिया और पति द्वारा बीना मुझसे कानुनी रूप से अलग हुए दुसरा विवाह करने का कहकर प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया। पीडित महिला ने बताया मेरी एक व दो वर्ष की दो मासुम लडकीया है और दोनो लडकियो के साथ मुझे घर से निकाल कर पीयर भेज दिया, मेरे पिता और मेरे भाई वापस मुझे समझा बुझाकर रूणजी मेरे सुसराल छोड़ने गए तो, मेरे सुसराल वालो ने मेरे साथ परिवार वालों के सामने मारपीट की गई, पीड़ित महिला के परिवार और ग्राम पचों द्वारा सुसराल वालो से सम्पर्क किया, लेकिन सुसराल वालो ने दूसरी महिला से बिना मुझे कानुनी तलाक लिए पत्नी बनाकर रख लिया है और अब मेरे परिवार को बोल रहे है कि, तुम्हारी लडकी तुम्हारे पास रखों यहाँ आई तो जान से मार देंगे। पीड़ित महिला पर स्वयं के साथ दो मासुम लडकियो के पालन-पोषण करने की मुश्किल खड़ी हो गई है। अब ये देखना होगा कि, पुलिस महिला की शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं या फिर एक और महिला प्रताड़ना का शिकार होकर फिर से गलत परंपरा की भेंट चढ़ जाएगी।

## पीएम मोदी के जन्मदिवस पर गरीब कल्याण सप्ताह में प्रत्येक जिले में मंत्री सहभागिता करें

# पीएम गौरवशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं, भारत बना है महाशक्ति

### मंत्रि-परिषद की बैठक में सीएम ने की मंत्रियों से चर्चा

भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में 16 सितंबर से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह में मंत्रियों को जन-कल्याण के कार्यक्रमों में सहभागिता करने को कहा है। यह कार्यक्रम निरंतर 8 दिन राज्य और जिला स्तर पर होंगे। फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन कार्यक्रमों से लाखों लोग जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने इन कार्यक्रमों से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश सभी विभागों को दिए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी एक या दो विभाग के न होकर राज्य सरकार के हैं। इनसे जन-जन के कल्याण का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। अतः कार्यक्रमों में प्रत्येक विभाग सक्रिय रूप से शामिल हों।

मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक प्रारंभ होने के पूर्व मंत्रियों से चर्चा करते हुए कहा कि 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस है। वह एक व्यक्ति नहीं संस्था हैं। उनके हृदय में बचपन से निर्धनों के प्रति करूणा का भाव रहा है। उनके बाल्यकाल से साहस के वृतांत जानने को मिलते रहते हैं। नरेन्द्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा और समाज सेवा के लिये जीवन अर्पित किया है। वे जिस भी संगठन से जुड़े, उसे गतिशील बनाया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा जब गुजरात की बेहाल दशा थी, तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने गुजरात की कायापलट कर दी। गुजरात मॉडल भी लोकप्रिय हो गया। मोदी कला, संस्कृति, इतिहास के अध्येता हैं। वर्ष 2014 से उन्होंने गौरवशाली, वैभवशाली और समृद्ध भारत के निर्माण के लिये प्रभावी कदम उठाये हैं।

### अपने साहस से सभी को कराया परिचित

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मोदी के सक्षम नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति बन गया है। सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण हो या चीन से जुड़ने का निर्णय, उन्होंने देश को बदल कर रख दिया है। अयोध्या के मामले के साथ ही कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का मामला हो अथवा तीन तलाक और नागरिकता कानून का विषय हो, उनके साहस से सभी परिचित हैं। वे राष्ट्रभक्ति के भाव से कार्य करने वाले मोदी

### पीएम के जन्मदिन पर कुपोषित बच्चों को बांटा जाएगा दूध

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में गरीब सप्ताह के अंतर्गत 16 सितम्बर से 23 सितम्बर तक विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम गरीबों की जिंदगी में प्रसन्नता के रंग भरेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि 16 सितम्बर को अन्न उत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आंगनवाड़ी केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को दूध बांटा जाएगा। इसी दिन सरचरों के उन्मुखीकरण और लाड़ली लक्ष्मी योजना की राशि का वितरण भी होगा। महिलाएं इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी।

### 18 को किसानों के खातों में जमा होगी फसल बीमा की राशि

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि 18 सितम्बर को 18 लाख किसानों के खातों में साढ़े चार हजार करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि जमा की जाएगी। इसी तरह 19 सितम्बर को वनाधिकार पट्टों का वितरण और 20 सितम्बर को स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिये उनको 150 करोड़ रुपए की राशि देने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि 21 सितम्बर को ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित किया जाएगा। जिसमें प्रति हितग्राही 10-10 हजार रुपए की ऋण राशि, कार्यशील पूंजी के रूप में प्राप्त कर अपने लघु व्यवसाय का उन्नयन कर सकेंगे।

### 22 सितंबर को किसान क्रेडिट कार्ड का होगा वितरण

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि गरीब कल्याण सप्ताह में 22 सितम्बर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण होगा। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण वितरण के लिये 800 करोड़ रुपए की राशि सहकारी बैंकों में जमा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि 23 सितम्बर को सम्बल योजना में हितग्राहियों को हित लाभ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह सभी कार्यक्रम कोरोना काल में एक साथ विभिन्न वर्गों को लाभान्वित कर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का कार्य करेंगे।

## सर्वदलीय बैठक के बाद नाथ का भाजपा पर निशाना, कहा-

# 35 दिन बाद हम ही बनाएंगे विस अध्यक्ष, प्रचार करेंगे तेज

### मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बाद अब कमलनाथ भी ग्वालियर दौरा करेंगे



भोपाल

मध्यप्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 35 दिन बाद हम ही विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे। कांग्रेस चंबल में चुनाव प्रचार तेज करेगी। कमलनाथ मंगलवार सुबह विधानसभा में सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। यह सत्र तीन दिन का बुलाए जाने को लेकर था। सरकार इस दौरान बजट, दस से ज्यादा बिल के साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराना चाह रही थी। ऐसे में कमलनाथ ने साफ कर दिया कि वे बजट बुलाए जाने के पक्ष में हैं, लेकिन अगर सत्र एक दिन से ज्यादा का होता है तो प्रश्न और ध्यानाकर्षण भी होगा।

### कमलनाथ भी ग्वालियर-चंबल में प्रचार करेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर-चंबल के दौरे के बाद अब कमलनाथ वहां का दौरा करेंगे। वहां 6 जिलों में 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। इधर, टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में मचे घमासान पर तंज कसते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। वह मानने को तैयार नहीं है।

### प्रश्न से बच रहे दोनों दल

काफी लंबी बातचीत के बाद सिर्फ एक दिन के सत्र में बजट पेश किए जाने पर सहमति बनी। सूत्रों की मानें तो दोनों ही पक्ष प्रश्नकाल से बचते नजर आए।

## नरोत्तम ने कांग्रेस को बताया डूबता जहाज

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की गहमा-गहमी के बीच बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी जारी है। इसी क्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब एक डूबता हुआ जहाज है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई भी नहीं रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता माने या न माने पर पार्टी में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। दरअसल, टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में फैले असंतोष पर नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा है।

### कांग्रेस ने किया पलटवार

वहीं, उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि मप्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण काल में भारतीय जनता पार्टी की उपचुनाव वाले क्षेत्रों में राजनीतिक रैलियां आयोजित करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है। चार महीने में 6000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया गया। जनता के ऊपर भार डाला गया।

### रिट्रोफिटिंग योजना में 34 लाख की राशि स्वीकृत

भोपाल। जल जीवन मिशन के अंतर्गत रिट्रोफिटिंग योजना में छतरपुर जिले के गौरिहार विकासखण्ड में 34 लाख 61 हजार रुपए की स्वीकृति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी की गई है। इसमें सकल स्त्रोत निर्माण, विद्युत सबमर्सिबल पंपों की स्थापना, जल वितरण नलिकाओं का बिछाना एवं जोड़ना आदि कार्यों की प्रक्रिया मैदानी स्तर पर प्रारम्भ की जा चुकी है।

### दांगी के निधन पर सीएम और मंत्री ने जताया दुख

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यावरा क्षेत्र के विधायक गोवर्धन दांगी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना ईश्वर से की है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने ब्यावरा विधायक गोवर्धन सिंह दांगी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

### पॉलीटेक्निक सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होगा शिवपुरी

भोपाल। शिवपुरी पॉलीटेक्निक कॉलेज को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जायेगा। सभी प्रकार के आधुनिक तकनीक से लैस यह कॉलेज एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यह बात तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने सोमवार को विभागीय गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कही। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आईटीआई को सशक्त और आकर्षक बनाना है।

## सर्वदलीय बैठक में लिया गया फैसला

# कोरोना के कारण तीन के बजाय एक दिन का होगा सत्र

### पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा- बजट का पास होना जरूरी है, पहले तीन दिन का होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे सीमित किया

भोपाल

मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों की सरगर्मी के बीच विधानसभा का एकदिवसीय सत्र 21 सितंबर को होगा। इस दौरान सिर्फ बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसका निर्णय मंगलवार सुबह विधानसभा में हुई सर्वदलीय बैठक में लिया गया। इस पर कांग्रेस ने भी अपनी सहमति दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बजट पास होना जरूरी है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ एक दिन का होगा। प्रश्नकाल नहीं होगा। अगर कोई सवाल आता है, तो उस पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि विधानसभा से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष समेत सभी दलों के लोग होते हैं। इसी दौरान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी किया जाएगा। सत्र में विदिन अरेंजमेंट और प्रश्नकाल के होने या नहीं होने पर चर्चा की गई।

### कमलनाथ पहले ही चिंता जाहिर कर चुके थे

मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पिछले गुरुवार को अचानक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने सीएम हाउस पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा, सीएम शिवराज और कमलनाथ के बीच उन विषयों को लेकर भी बातचीत हुई, जिनकी चर्चा विधानसभा सत्र के दौरान होने वाली है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 21 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र तीन दिन का होगा, जो 23 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने सत्र को लेकर चिंता भी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ बजट पर सहमत हुए हैं।

### इसलिए एक दिन का सत्र

- मौजूदा स्थिति में 108 विधायक ही बैठ सकते हैं।
- प्रदेश में कई विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं
- दो सत्रों के बीच छह महीने की संवैधानिक अनिवार्यता के कारण दिन का समजूलाय गया।
- सत्र में सिर्फ बजट पास किया जाएगा।
- दर्शक दीर्घा में विधायकों को बैठाया जा सकता है।
- अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी सीमित की जाएगी।

## सूची फाइनल कराने 19 को दिल्ली जाएंगे कमलनाथ

# कांग्रेस अगले हफ्ते जारी कर सकती है अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट

### 15 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों को लेकर हो रहा है विरोध

भोपाल

मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी के 15 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों को लेकर हो रहे विरोध के बीच कांग्रेस पार्टी ने दूसरी सूची को लेकर मंथन तेज कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ 19 सितंबर को ग्वालियर से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कमलनाथ पार्टी नेताओं से मुलाकात कर दूसरी सूची को फाइनल करेंगे। जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी 22 सितंबर तक अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। वहीं, कांग्रेस पार्टी की पहली सूची के विरोध होने



के बाद दूसरी सूची को लेकर दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं।

कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासत भी गर्म हो उठी है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, उनमें गोहद से मेवाराम जाटव का पार्टी नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं। टिकट के दावेदार भिंड जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया ने समाजवादी पार्टी से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। वहीं, सांची सीट पर मदन लाल चौधरी को उम्मीदवार बनाए जाने पर भी विरोध हो रहा है। सांची सीट पर प्रभात साहू, डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी और हेमंत मारवरिया ने विरोध जताया है। ग्वालियर से सुनील शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज हैं। डबरा से सुरेश राजे को उम्मीदवार बनाने पर सत्य प्रकाश परसेडिया ने मोर्चा खोल दिया है।

### बीजेपी ने कसा तंज

कांग्रेस की सूची पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस में उम्मीदवारों के विरोध के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा नाम तय करने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मूल कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बाहरी को उम्मीदवार बनाए जाने पर उपचुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना होगा। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची पर हो रहे विरोध के बाद दूसरी सूची जारी करने को लेकर कवायद तेज कर दी है और मुमकिन है कि उप चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस पार्टी बाकी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे।

## नियमितकरण पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

# उपचुनाव से पहले भाजपा के लिए मुसीबत बन सकते हैं अतिथि विद्वान

भोपाल

मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष का आरोप है कि अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण के आंदोलन में भाजपा के बड़े नेताओं ने सत्ता में वापिस आने पर नियमितीकरण के सपने दिखाए और सत्ता में वापिस आते ही वादा पूरा करना ही भूल गए। सत्ता से जाते जाते पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की नोटशीट तैयार की थी, जिससे अतिथि शिक्षक नियमित हो सके पर अब भाजपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव नोटशीट को ही बेवकूफ बनाने का कागज बता रहे हैं।

### नोटशीट पर बढ़ रहा विवाद

अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की नोटशीट पर विवाद बढ़ता जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि ऐसी कई कागज बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। अगर पूर्व कांग्रेस सरकार कर सकती थी तो डेढ़ साल में क्यों नहीं किया। बोलने की बात अलग है, मैदान में करने की बात अलग है। हम लोग ठोस काम करने वाले लोग हैं। मेरी पूरी सद्भावना अतिथि विद्वानों के साथ है।

## उमा भारती ने दी कमलनाथ को सलाह, कहा

# कांग्रेस को विपक्ष में रहना नहीं आता तो हमसे ले ट्रेनिंग

ग्वालियर

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने प्रदेश में कांग्रेस द्वारा सिंधिया के विरोध पर कमलनाथ को सलाह दी है। उन्होंने ग्वालियर में कहा कि आपका विरोध लोकतांत्रिक होना चाहिए। अगर आपको विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आता तो हम आपको विपक्ष में रहने की ट्रेनिंग देंगे। वहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के उद्धव ठाकरे के अयोध्या आगमन को लेकर दिए बयान पर उमा ने कहा कि अयोध्या और राम बीजेपी या हिन्दू समाज की प्रॉपर्टी नहीं है।

### मर्यादाओं का करना चाहिए पालन

ग्वालियर में बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अटल जी से लेकर हमने लंबे समय विपक्ष की भूमिका निभाई है। कमलनाथ जी बहुत शालीन व्यक्ति हैं। उनसे कहूंगी कि कमलनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए। जो लोग आपकी पार्टी को छोड़ कर चले गए हैं, वह आप की कमियों की वजह से गए हैं। उस पर आत्म चिंतन करिए।

# केन-बेतवा लिंक परियोजना से खेतों तक पहुंचेगा पानी

भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उनका सर्वे कर हरसंभव सहायता की जाएगी। किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृत कर छतरपुर जिले के प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले की तहसील बड़ामलहरा के ग्राम सिंघौरा में काठन वृहद सिंचाई परियोजना के भूमिपूजन एवं हितग्राही सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने इस अवसर पर 544 करोड़ रुपए की लागत विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया।



जिसमें 394 करोड़ रुपए की काठन सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन भी शामिल है। इस परियोजना से 74 गांव के 15 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

## पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की राज्य सड़क सुरक्षा सेल की रिपोर्ट में खुलासा

# कोरोना काल में मध्य प्रदेश में कम हुए सड़क हादसे

भोपाल

मध्यप्रदेश में सड़क हादसों की रफ्तार को कोरोना ने रोक दिया है। इस बात की जानकारी पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की राज्य सड़क सुरक्षा सेल की ताजा में सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना काल में सड़क हादसों की संख्या और उससे होने वाली मौत और घायलों की संख्या में कमी आई है।

पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की राज्य सड़क सुरक्षा सेल की प्रभारी प्रज्ञा जोशी ने बताया कि सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौत और घायलों की संख्या में कोरोना के कारण कमी आई है।

कोरोना के कारण प्रदेशभर में लॉकडाउन लगाया गया था। समय-समय पर रियायत जरूर दी गई, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी से सड़क पर तैनात होकर काम किया। बैरिकेड लगाकर चेकिंग की गई। रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद किया गया। कई रास्तों को दूसरे रास्तों पर डायवर्ट किया गया। पुलिस की मुस्तैदी और प्लानिंग की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चली। मार्च से कोरोना आपदा शुरू हुई थी और ऐसे में चार महीनों में सड़क हादसों में कमी आई है।

### मौत का आंकड़ा हुआ है कम

प्रज्ञा जोशी ने कहा कि यह अच्छी बात है कि सड़क हादसों में पिछले साल की तुलना में इस साल 6 महीनों के अंदर भारी कमी आई है। हादसे में होने वाली मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है और हादसों की संख्या में भी भारी कमी आई है। जोशी ने बताया कि पुलिस की प्लानिंग आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। हादसों को कम करने और सुरक्षा के उपायों को जारी रखने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के करीब 4 जिले ऐसे हैं, जहां पर कोरोना वायरस के दौर में भी हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन जिलों को वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हादसों को कम करने और उस पर कंट्रोल करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

### ये है 6 महीने की स्थिति

राज्य सड़क सुरक्षा सेल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 30 जून 2019 और 2020 की तुलनात्मक अध्ययन में कई खुलासे हुये हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के शुरुआती छह महीनों में सड़क हादसों की संख्या 27578 थी, जबकि 2020 में यह संख्या 19724 हो गई। यानी 28.48 प्रतिशत हादसों में कमी आई है। 2019 के 6 महीनों में सड़क हादसों में कुल 6234 मौत हुई है, जबकि 2020 में मौत का आंकड़ा 4716 तक पहुंचा है। यानी सड़क हादसों में मौत में 24.4 फीसदी की कमी आई है। वहीं घायलों की संख्या 2019 के शुरुआती छह महीनों में 29264 थी, जबकि 2020 में यह संख्या 20674 हो गई। इस हिसाब से सड़क हादसों में घायलों की संख्या 2019 की तुलना में 2020 में 29.4 फीसदी कमी आई है।

# पुलिस के साथ ग्रामीणों ने की रात्रि गश्त शुरू

**माही की गूंज , झकनावदा।** झकनावदा क्षेत्र में चोरी की वारदात बढ़ रही है जिसे देख चौकी प्रभारी जीएस मावी ने ग्रामीणों को बताया कि, चौकी क्षेत्र मैं करीब 36 गांव लगते हैं, क्षेत्र काफी बड़ा होने से हम पूरे क्षेत्र में रात्रि गश्त लगाने में असक्षम है, इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के नगर सुरक्षा समिति प्रमुखों को बुलवाकर उन्हें कहा कि, रात्रि गश्त में अपने-अपने वार्ड, फलिया और मोहल्ले में सभी गश्त कर पुलिस की मदद करें। इस अवसर पर क्षेत्र में बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए प्रधान आरक्षक उमेश पुरोहित, प्रधान आरक्षक रईस खान, आरक्षक पंकज राजावत, मनोहर सहित रात्रि में युवाओं के साथ पुलिस गश्त लगा रहे हैं।

# 15 वर्षीय बालक की सांप के काटने से हुई मृत्यु

**माही की गूंज, झाबुआ।** शहर के समीपस्थ ग्राम करड़ावद बड़ी में एक 15 वर्षीय बालक को बीती रात अपने घर पर सोते समय खाट के ऊपर चढ़कर कान पर सांप ने काट लिया। जिसके बाद बालक को परिवाजनों द्वारा उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। जहां ईलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। दोपहर में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घटना मे पुलिस थाना झाबुआ पर मर्ग कायम किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम करड़ावद बड़ी निवासी अनिश पिता पारू डामोर रात को अपने घर में ही खाट पर सोया। तभी अलसुबह 6 बजे खाट पर सांप ने चढ़कर बालक के कान पर काट लिया। अनिश ने संर्पदंश के बाद तुरंत सांप को हाथ से उठाकर दूर फैंका। जिसके बाद परिजनों को बताया। परिजन उपचार के लिए उसे जिला चिकित्सालय लेकर आए। जहां चिकित्सक द्वारा ईलाज करते समय उसकी मृत्यु हो गई।

### प्रशासन से की आर्थिक सहायता की मांग

बालक भील एकेडमी झाबुआ में कक्षा 6 टीं में पढ़ता था। पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर परिजनों तथा ग्रामवासियों की भीड़ जमा हो गई। घटना में पुलिस चौकी बस स्टैंड के एएसआई खलील अहमद पठान ने मर्ग कायम कर शव का चिकित्सक से पोस्टमार्टम करवाया। जिसके बाद शव को ग्रामवासी निजी वाहन से अपने गांव ले गए। बालक के परिजनों द्वारा जिला प्रशासन से अनिश की असामायिक तथा सर्पदंश से मृत्यु होने से आर्थिक सहायता की मांग की है।

**सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस**

# दूसरे दिन रैली निकालकर व्यापारियों को पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने संबंधी पत्रक किए वितरित

## भाजपा मंडल ने बस स्टैंड पर किया सभा का आयोजन, 20 सितम्बर तक होंगे प्रतिदिन अलग-अलग आयोजन

**माही की गूंज, झाबुआ।**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस को प्रदेश भाजपा संगठन एवं जिला भाजपा के निर्देश पर शहर में भाजपा मंडल झाबुआ द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। जिसके तहत 14 से 20 सितंबर तक प्रतिदिन अलग-अलग कार्यक्रम किए जा रहे है। दूसरे दिन 15 सितंबर मंगलवार को दोपहर शहर में पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया गया। राजवाड़ा से ''पॉलथीन मुक्त शहर'' रैली निकाली गई। रैली मार्गो पर व्यापारियों को पत्रक वितरित कर अपनी दुकानों पर पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने हेतु समझाईश भी दी। रैली के बस स्टैंड पहुंचने पर सभा का आयोजन हुआ।

जानकारी देते हुए भाजपा मंडल झाबुआ के अध्यक्ष दीपेश बबलू सकलेचा ने बताया कि, मंगलवार को दोपहर साढ़े 12 बजे राजवाड़ा से रैली आरंभ हुई। जिसमें आगे प्रधानमंत्री के जन्मदिवस का बेनर लेकर युवा कार्यकर्ता चले। इसके पीछे महिलाएं अपने हाथों में ''पॉलिथीन मुक्त शहर'' बनाने की तख्तीयां लेकर शामिल हुई। साथ ही अन्य भाजपाजनों के हाथों में पार्टी के झंडे थे। यह रैली शहर के नेहरू मार्ग, मनोकामना तिराहा, आजाद चौक, बाबेल चौराहा, थांदला गेट, मेन बाजार, फव्वारा चौक होते हुए बस स्टेंड पहुंची।

### व्यापारियों को वितरित किए पत्रक

रैली के दौरान भाजपाईयों द्वारा दुकानों पर जाकर व्यापारियों सहित राह चलते लोगों और वाहन चालकों को भी पत्रकों का वितरण किया गया। जिसमें दुकानदारों से अपनी दुकानों पर पॉलिथीन का उपयोग नही करते हुए ग्राहकों को कागज और कपड़ों से बनी पॉलिथीन में सामग्रीयां देने तथा लोगों को भी पॉलिथीन के हानिकारक प्रभाव बताते हुए इसका उपयोग नहीं करने हेतु समझाईश दी। पत्रक में प्लास्टिक पॉलिथीन उपयोग के दुष्परिणाम बताते हुए इसे समाज एवं देश के लिए काफी घातक बताया एवं सभी से संकल्प दिलवाया कि, हम अब भविष्य में पॉलिथीन का उपयोग नहीं करते हुए कागज और कपड़ों की पॉलिथीन का उपयोग करेंगे तथा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे।





### प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत का सपना

रैली के बस स्टेंड पहुंचने पर यहां सभा हुई। जिसको संबोधित करते हुए सर्वप्रथम भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक, ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश को ''स्वच्छ और स्वस्थ'' बनाने का जो सपना देखा गया, उसको हम सभी को मिलकर पूरा करना है। यह हमारे के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने कार्यकाल में देश में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उनके उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व जिलाध्यक्ष दौलत भावसार ने कहा कि, केंद्र सरकार और मप्र में भाजपा सरकार द्वारा कोरोनाकाल में भी गरीब मजदूरों, किसानों, ठेला व्यवसाईयों की मद्द करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की है। सभा का संचालन करते हुए भाजपा मंडल झाबुआ अध्यक्ष दीपेष बबलू सकलेचा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के बारे में जानकारी देते हुए आगामी दिनों में मंडल द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। अंत में आभार भाजपा मंडल महामंत्री हेमेन्द्र नाना राठौर ने माना।

### यह रहे उपस्थित

इस अवसर पर विषेश रूप से भाजपा जिला महामंत्री प्रवीण सुराना, जिला उपाध्यक्ष अजय पोरवाल, जिला मंत्री संगीता पलासिया, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धनसिंह बारिया, पूर्व नपा उपाध्यक्ष विजय चौहान, वरिष्ठ भाजपा नेता रमेष शर्मा, सेवा सप्ताह प्रभारी एवं पार्षद जुवानसिंह गुंडिया, भाजपा मंडल झाबुआ के पदाधिकारी अंकुर पाठक, महेष वर्मा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरू भूरिया, अमरू डामोर, जितेन्द्र जैन, बिट्टू सिंगार, भारत बामनिया, मजेसिंह, अभाविप के मांगीलाल भूरिया, राजा ठाकुर, योगेन्द्र नाहर, राजू थापा, आईटी सेल के जिला संयोजक अर्पित कटकानी, ओम भदोरिया, कार्तिक हटिला, भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री सायरा खान, शोभा कटारा, रमिला निनामा, श्रीमती भगोरा, सुनिता वर्मा आदि सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

## प्लास्टिक उपयोग नही करने के लिए किया जागरूक

**माही की गूंज, झकनावदा। आनंद सोलंकी**



ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वे जन्म दिवस के उपलक्ष में सात दिवसीय जन हितेषी कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार मंगलवार को झकनावदा बस स्टैंड पर स्थित किराना दुकानों पर प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत कपड़े की थैलियों का वितरण पूर्व युवा मोर्चा जिला मंत्री अभय जैन के नेतृत्व में किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को समझाइश दी गई की आगे भी आप लोग ग्राहकों के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें और दूसरों को भी न करने दें, पॉलिथिन के कारण बेकसूर जानवर के शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और वह बीमार होकर मर जाते हैं। इस अवसर पर युवा मोर्चा पूर्व जिला मंत्री अभय जैन, राकेश लछेटा, लक्ष्मण चौधरी, मंडल मंत्री वीरेंद्र गोस्वामी, वासुदेव जमादारी, श्याम श्रीवास्तव, गोपाल चौधरी, निलेश सोनी एवं आनंद प्रजापत आदि उपस्थित थे। झकनावदा के भाजपा नेताओं द्वारा लगातार अभियान के तहत अलग-अलग तरीके से काम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे है।

# अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत अन्न उत्सव में 42 नवीन लाभार्थियों को पात्रता पर्ची का वितरण किया गया

**माही की गूंज, झकनावदा।**



अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन पूरे मध्यप्रदेश में 37 लाख नवीन लाभार्थियों को राशन वितरण हेतु पात्रता पर्ची का वितरण किया गया, उसी क्रम में ग्राम पंचायत झकनावदा में 16 दिसंबर को लाइव कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नवीन उपभोक्ताओं को संबोधित किया, साथ ही उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा 42 नवीन लाभार्थियों को पात्रता पर्ची का वितरण किया गया व मुख्यमंत्री का सीधा प्रसारण में ग्राम पंचायत सचिव सहित जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पात्रता पर्ची एवं मुख्यमंत्री के सीधा प्रसारण आयोजन में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्रीमती दुर्गा पडियार, सांसद प्रतिनिधि राजेश कांसवा, ओम प्रकाश सेमरोड, नरेंद्र राठोड़, वरिष्ठ भाजपा नेता मांगीलाल पडियार, मोहनसिंह राव, सचिव भीमसिंह कटारा सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

### अन्न उत्सव मनाया गया

माही की गूंज , जामली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में लाभार्थियों को ग्राम जामली में भी राशन वितरण किया गया। सेल्समैन महेंद्रसिंह राठौर ने बताया कि, आज के दिन सभी उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत अन्न उत्सव मनाया जा रहा है, उसी योजना के अंतर्गत आज हम यहां राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं जिससे सभी गरीब परिवारों को अनाज दिया जा रहा है।



# राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की जिला स्तरीय बैठक सूजापुर में हुई संपन्न

**माही की गूंज, रतलाम।**





राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की जिला स्तरीय बैठक सूजापुर में संपन्न हुई जिसमे सेना के वरिष्ठजनो ने बताया कि, नवी सूची में आरक्षण के विरोध में पुरे मध्यप्रदेश मे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से लोगों को यह बताया जा रहा है कि, नवी सूची में आरक्षण अगर हो जाता है तो उसके क्या परिणाम होंगे।

### क्या है 9वी अनुसूची

9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है, जिसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं, जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जीवन सिह शेरपुर, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की हमेशा ही है मांग रही है कि, आरक्षण आर्थिक आधार पर हो उसके अलावा एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन जैसे बड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसके अलावा हम ने अभी-अभी सरकार से मांग की है कि, पुलिस बल का वेतन भी बढ़ाया जाए क्योंकि वह दिन-रात सेवा में लगे रहते हैं, अतिथि शिक्षक का मुद्दा भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश के पटल पर उठा रही हैं जिससे उनकी आवाज बुलंद करने में मदद मिले एवं जीस परेशानियों व तकलीफो से वह लोग गुजर रहे हैं उसका निवारण जल्द से जल्द किया जाए। करणी सेना के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष लोकेंद्रसिंह पाताखेड़ी, संभाग प्रभारी पुष्पेंद्रसिंह, केरवासा तहसील अध्यक्ष रविराजसिंह, कमलेंद्रसिंह, जावरा नगर के अध्यक्ष हरेंद्रसिंह तोमर, विधानसभा प्रभारी विक्रमसिंह सोलंकी, हरेंद्रसिह तोमर, अंतरसिह डोडीया, रणजीतसिह डोडीया सहित सैकड़ो की तादात मे करणी सेनीक सभा में उपस्थित थे।

# झाबुआ की निधि सारोलकर पूरे देश में कर रही नाम रोशन, 'इंडियन आईडियल' के लिए हुआ सिलेक्शन

**माही की गूंज, झाबुआ।**



शहर की होनहार युवती निधि सारोलकर शास्त्रीय संगीत में पारंगत होकर न केवल झाबुआ जिले, अपितु मप्र और देश में भी अपना नाम रोशन कर रही है। निधि का चयन हॉल ही में सोनी टेलीविजन पर आने वाले फेमस शो 'इंडियन आईडियल' के लिए भी हुआ है। उनके द्वारा इस विद्या में अब तक झाबुआ जिले, मप्र तथा अन्य राज्यों में प्रस्तुति देकर कई पुरस्कार भी प्राप्त किए जा चुके है। साथ ही नेशनल लेवल पर भी वह अपनी परफारमेंस दे चुकी है। सोमवार शाम को उन्होंने स्वर योग कला एकेडमी के माध्यम से फेसबुक पर अपनी लाईव प्रस्तुति दी, जिसे हजारों लोगों ने देखा और पसंद किया।

झाबुआ के कुरैशी कपांउड में रहने वाली निधि को बचपन से ही शास्त्रीय संगीत (गायन) में रूचि थी, उनका सपना भी इस विद्या में भविष्य में अपना कॅरियर बनाने का है। वर्तमान में इंदौर में स्थित माता जीजाबाई कॉलेज से 'शास्त्रीय हिन्दूस्तानी संगीत' की मास्टर डिग्री प्राप्त कर रही है। उनकी गुरू स्वर योग कला एकेडमी इंदौर की प्रमुख वैशाली बकोरे है। जिनका उन्हे समय-समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। इसके साथ ही उन्हें इस कार्य में अपनी माता प्रिया सारोलकर, पिता विजय सारोलकर तथा बड़े भाई रोहित का भी विशेष सहयोग प्राप्त होता है। वह उन्हें समय-समय पर इस हेतु प्रेरित करने के साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी करते रहते है।

### फेसबुक पर दी लाईव प्रस्तुति

युवा निधि ने स्वर योग एकेडमी इंदौर की संचालिका वैशाली बकोरे से मार्गदर्शन तथा प्रेरणा लेकर ही सोमवार को फेसबुक पर अपनी लाईव प्रस्तुत दी। करीब 45 मिनिट तक निधि ने अलाप प्रस्तुति दी। उनकी इस परफारमेंस को फेसबुक पर लोगों ने शेयर, लाईक करने के साथ सकारात्मक कमेंट भी किया। वह समय-समय पर अपनी परफारमेंस देती रहती है और लोगों की वाहवाही लेती रहती है।

# दो घरो में चोरी के बाद ट्रेक्टर भी ले गए चोर

**माही की गूंज रायपुरिया। उमाशंकर पाटीदार**

रायपुरिया में सोमवार व मंगलवार की रात में अपने घर से कुछ ही दूर घर के बाहर रोज कि तरह ट्रैक्टर खड़ा कर सो गए थे, जिसे चोरों ने चोरी कर लिया।

जानकारीनुसार गांव के पुराने बिजली ऑफिस के पास रहने वाले सुंदरलाल पाटीदार ने बताया कि, रात्रि 9 बजे मेरे घर के सामने ट्रैक्टर खड़ा किया गया था, लेकिन हम मेरे दूसरे मकान पर सोए हुए थे। अज्ञात चोरों ने घर की मुख्य दीवार को सेंधमारी कर रहे थे, तो जाग जाने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसके बाद घर से बाहर निकल कर देखा तो नंदु पिता शंभु का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 45 एसी 0121 वहां से चोरी हो गया था। रात्रि में ही इधर-उधर खोजने की कोशिश की लेकिन अभी तक ट्रेक्टर का कोई पता नही चला। लगातार गांव में चोरी होने से गांव में दहशत का माहौल है, आधे से ज्यादा गांव में ग्रामीण जन अपने-अपने मोहल्ले में रात्रि गस्त कर रहे हैं।

### चोरों ने एक मोहल्ले के तीन घरो में बोला था धावा

ट्रेक्टर चोरी के पूर्व भी एक रात में ही चोरों ने ग्राम के एक ही मोहल्ले में तीन जगह एक साथ चोरी को अंजाम देकर लाखो का माल लेकर फरार हो गए थे, चोरों ने हरिओम पाटीदार, दयाराम पीरु और जगदीश पिता मानसिंह के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अगल-अलग जगह से नकदी और सोना और चांदी मिलकर करीब चार लाख के आसपास की चोरी हुई। एक स्थान पर चोर असफल हुए, जहा मवेशी भी थे पर मवेशी निकालने में असफल रहे ।

# नियमों का पालन नहीं, सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम

## सड़कों पर लोग बिना दुरी व बिना मास्क के बेफिक्र होकर घूम रहे

**माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय**



कोराना से आमजन को बचने-बचाने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन प्रभावशील कर शासन ने चेन तोड़ने की कोशिश की लेकिन लोगों को 5 माह तक जागरूक करने के बाद भीं शासन की तमाम कोशिशें नाकाम रही, लोग बेफिक्र होकर बिना मास्क के घरों से निकलकर सड़कों पर घूम रहे हैं, बगैर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी के कारण कोरोना मरीज दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, शासन की अनलॉक 4 की गार्डलाइन आने के बाद लोगों को यह लगने लग गया है कि, अब कोरोना खत्म हो गया है, सार्वजनिक स्थानों होटलों व अन्य भीड़भाड़ के स्थानों पर ऐसा लगता है कि, साप्ताहिक हाट बाजार लगा हो प्रतिदिन भीड़ सड़कों पर बिना मास्क एवं सामाजिक दूरी के उमड़ रही है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आने वाले ग्राहकों का कोई सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, व्यापारी भी बिना मास्क के व्यापार कर रहे हैं, ऐसी लापरवाही कोविड-19 संक्रमण महामारी के परिणामों को समझने के बाद भी हो रही है।

अब सारंगी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में भी संक्रमण के मरीज मिल रहे है, जिसमें कई लोग संदिग्ध होने के बाद बड़े नगरो की ओर रुख कर निजी हॉस्पिटलों में जाकर कोविड सैंपलिंग करवा रहे है, अनलॉक 4 की गाइडलाइन आने के बाद प्रशासन भी बेफिक्र हो गया है, किसी को भी संक्रमण से बचाव को लेकर रोकने-टोकने वाला नहीं है, जिससे आमजन बिना मास्क व सामाजिक दूरी से बेपरवाह होकर बेधड़क घूम रहे हैं, इस महामारी के बचाव के मानकों को लेकर हो रही लापरवाही आम जनमानस पर निश्चित ही भारी पडेगी।

संपादकीय

## कोरोना के खतरे के बीच संसद की कार्यवाही गणतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास का उदाहरण

हम पहली बार देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई है। यह निर्णय और प्रयास स्वागत योग्य है और गणतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास को मजबूत करता है। बेशक सावधानियां बरती गई हैं। देश सतर्क भी है, लेकिन महामारी के खतरे अपने ही हैं। सांसदों को किट्स बांटी गई हैं। प्रत्येक किट में 40 डिस्पोजल एन-95 मास्क, सेनिटाइजर की 20 बोतलें, 40 गलब्स और दरवाजा बंद करने के लिए टच फ्री हुक्स आदि को रखा गया है। सावधानियों के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 50 लाख को छू रही है। करीब 80,000 मौतें हो चुकी हैं। सितंबर के पहले 12 दिनों में ही 10 लाख संक्रमित मरीज सामने आए और 13,000 से ज्यादा मौतें हुई।

दुनिया में कोरोना से हररोज जितनी मौतें हो रही हैं, उनका एक-चौथाई भारत में ही हैं। बेशक संक्रमण के आधार पर भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, लेकिन अमरीका और ब्राजील से तीन गुना ज्यादा संक्रमित मरीज भारत में हररोज मिल रहे हैं और मौतें भी लगभग दुगुनी हो रही हैं। ऐसा लगता है मानो हमारा जन-स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा ही चरमरा गया हो! ऐसे भयावह संक्रामक परिवेश में संसद के मानसून सत्र का आगाज हुआ है, तो यकीनन तय है कि कोरोना के साथ-साथ जिंदगी भी चलेगी, कोरोना का सामना किया जाएगा, तो संसद अपना गणतांत्रिक दायित्व भी निभाएगी। संसद परिसर में बड़े अजीब, आत्यशित बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल को बंद किया गया है। जिन दीर्घाओं में आम दर्शक और पत्रकार बैठते थे, वहां अब सांसद बैठेंगे। करीब 300 पत्रकारों के बजाय सिर्फ 39 को ही दीर्घा तक जाने की अनुमति दी गई है। पत्रकारों को बारी-बारी से जाने और बैठने की अनुमति होगी। अलबत्ता समाचार एजेंसियों आदि के सात पत्रकारों को स्थायी तौर पर छूट दी गई है।

संसद भवन में कई जगह आने-जाने पर पाबंदी लगाई गई है। राज्यसभा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी और लोकसभा की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। यानी सिर्फ 4 घंटे की संसदीय कार्यवाहीः कुल 18 बैठकों के दौरान 47 बिल पारित किए जाने हैं। इनमें 11 अध्यादेश होंगे, जिन्हें अब बिल के तौर पर पारित किया जाएगा। यह भी बीते 2-3 दशकों के दौरान पहली बार देखा गया है कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी नहीं की गई। प्रश्नकाल और निजी विधेयक की व्यवस्था तो पहले ही खारिज की जा चुकी थी। लिहाजा यह संसद सत्र आधा-अधूरा ही होगा। हालांकि कोरोना वायरस, चीन, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी आदि मुद्दे बहसतलब होने चाहिए, लेकिन नई बंदिशों में सांसद अपना विरोध कैसे जता पाएंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विपक्षी सांसदों की अध्यक्ष के आसन तक जाने और नारेबाजी कर हंगामा बरपाना आदत-सी रही है। इधर एक बड़ी खबर उद्घाटित हुई है कि चीन की कंपनियां 10,000 से अधिक भारतीय और संगठनों की जासूसी करवा रही हैं और एक डाटाबेस तैयार कर रही हैं।

इनमें 5 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व एवं मौजूदा राज्यपाल, 350 के करीब सांसद, सेना के पूर्व एवं मौजूदा बड़े अधिकारी और चीफ, प्रधान न्यायाधीश, पत्रकार, उद्योगपति आदि शामिल हैं, जिनके जरिए संवेदनशील सूचनाएं इकट्ठा करने की साजिश रची गई है। यकीनन यह देश की सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर विषय है, लिहाजा महत्तवपूर्ण होगा कि संसद में इस पर कैसी और कितनी गंभीर बहस होती है और संसद किस आशय का प्रस्ताव पारित करती है? संसद में मुंबई का हालिया ड्रग्स मामला तो उठाया गया है। बहरहाल संसद से जुड़े 4000 से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। 65 साल की उम्र से अधिक के सांसदों ने खुद ही तय किया है कि वे कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। ईश्वर इस प्रयास को सुरक्षित रखे और कामयाबी दे, ताकि विधायी और संसदीय कामकाज किया जा सके।

# ड्रेगन पर भारी भारतीय जांबाज

योगेश कुमार गोयल

पिछले चार महीने से पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए मास्को में भारत-चीन के विदेश मंत्रियों के बनी पांच सूत्रीय सहमति के बाद कहा जा रहा है कि यदि तय बिन्दुओं के अनुरूप वार्ता आगे बढ़ती है तो इसके सार्थक परिणाम हो सकते हैं। अब दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता की शेष सभी की नजरें केन्द्रित हैं लेकिन परेशानी यह है कि दोनों देशों के बीच कॉर्प कमांडर स्तर की वार्ताओं के पहले भी कई दौर हो चुके हैं। चीन हर बार तनाव घटाने के लिए तय किए जाने वाले कई मुद्दों पर सहमति प्रकट करता रहा है लेकिन जब उसपर अमल की बात आती है तो वह सारा ठीकरा भारतीय सेना पर फोड़कर मुकर जाता है। हालांकि अब वार्ताओं के इन दौर के बीच चीन को भारत की ओर से स्पष्ट संकेत दिए जा चुके हैं कि चीनी सेनाओं द्वारा पीछे हटने की स्थिति में ही भारत पीछे हटने पर विचार करेगा। हाल ही में अमेरिकी अखबार न्यूजवीक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय सैनिक निर्भीकता से नएपन का प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में जिस प्रकार हमारे जांबाज सैनिकों द्वारा ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा किया गया है, उससे चीनी सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा है। उसके पास पीछे हटने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है लेकिन उसकी फितरत हमेशा धोखे और वादाखिलाफी की रही है, इसीलिए भारत द्वारा एक-एक कदम फूंक-फूंककर रखना बेहद जरूरी है।

चीनी सेना (पीएलए) पूर्वी लद्दाख में कायम गतिरोध पर सैन्य और राजनयिक वार्ता के जरिये बनी आम सहमति का बार-बार उल्लंघन करती रही है। घुसपैठ की कोशिशों के बीच चीन ने सीमा के आसपास अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाया है और तमाम हथियार तैनात किए हैं। टकराव की आड़ में ड्रैगन एलएसी के करीब अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है और इसीलिए भारत द्वारा भी अब अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक पूरे इलाके में एलएसी पर सेना को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। वायुसेना द्वारा रात के समय भी गश्त बढ़ाकर पहले ही ड्रैगन को संदेश दिया जा चुका है कि वह पर्वतीय इलाकों में उसके किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अपाचे और चिनूक जैसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर एलएसी के आसपास कड़ी निगरानी कर रहे हैं। सुखोई, जगुआर तथा मिराज जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान पहले से ही लद्दाख इलाके में तैनात हैं। इनके अलावा मिग-29के की स्क्वाड्रन भी वहां तैनात की जा चुकी है।

जमीनी और हवाई मोर्चे के अलावा भारत अब समुद्र में भी ड्रैगन की घेराबंदी करने में जुट गया है। उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा बेहद गोपनीय तरीके से दक्षिण चीन सागर में अग्रिम मोर्चे के अपने युद्धपोत की तैनाती कर दी गई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों और सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध की स्थिति में भारत उत्तरी सीमाओं पर ड्रैगन पर भारी पड़ सकता है। दोनों देश आज जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। भारतीय नौसेना में 2013 में शामिल किए गए लगभग तीन फुटबॉल मैदानों के बराबर लंबे तथा करीब 22 मंजिली इमारत जितने ऊंचे आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत पर तैनात कामोव-31, कामोव-28, हेलीकॉप्टर, मिग-29-के लड़ाकू विमान, ध्रुव, चेतक हेलीकॉप्टरों सहित तीस विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियों के चलते इसके एक हजार किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत फटक भी नहीं सकते। 32 नॉट (59 किलोमीटर प्रतिघंटा) की रफ्तार से गश्त करने वाला यह युद्धपोत लगातार सौ दिनों तक समुद्र में रह सकता है। इसके अलावा 2012 में रूस से करीब एक अरब डॉलर के सौदे पर दस वर्ष के लिए लीज पर ली गई भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस चक्र-2 परमाणु हमला करने में सक्षम है। समुद्र में इसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रतिघंटा है और पानी के अंदर 600 मीटर गहराई तक लगातार तीन महीने तक रह सकने वाली यह पनडुब्बी पलक झपकते चीन और पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकती है।

स्लोबल फायरपावर के अनुसार दुनिया की शक्तिशाली वायुसेना के मामले में चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। चीन के पास भारत के मुकाबले में दो गुना लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान हैं, भारत से दस गुना ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर हैं लेकिन चीनी वायुसेना भारत के मुकाबले मजबूत दिखने के बावजूद भारत का पलड़ा उस पर भारी है। दरअसल भारतीय लड़ाकू विमान चीन के मुकाबले ज्यादा प्रभावी हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत ने चीन से लगी सीमा पर कई हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, जहां से हमारे फाइटर जेट आसानी से उड़ान भर सकते हैं। हालांकि चीनी वायुसेना भी भारत से लगी सीमा क्षेत्र में आठ ठिकानों का उपयोग करती है लेकिन इनमें से अधिकांश नागरिक हवाई क्षेत्र हैं, जहां से चीन को हमला करने में परेशानी हो सकती है। भारत के राफेल, मिराज-2000 और एसयू-30 जैसे जेट विमान किसी भी मौसम में और कैसी भी परिस्थितियों में उड़ान भर सकते हैं जबकि चीन के जेट विमानों जे-11 और एसयू-27 में इतनी ताकत नहीं है। चीन के पास एस-300 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, वहीं भारत के पास ब्रह्मोस के अलावा कई दूसरी घातक मिसाइलें हैं। इसके अलावा भारत के पास दस सी-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट हैं, जो एक बार में 4200 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक 40-70 टन के पेलोड ले जाने में सक्षम हैं।

बेलफर सेंटर के अध्ययन के अनुसार चीन ने भारत से लगी सीमा पर जे-10, जे-11 और एसयू-27 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है लेकिन भारतीय वायुसेना के मिराज-2000 और सुखोई एसयू-30 लड़ाकू विमानों को इन पर बढ़त हासिल है। मिराज-2000 और एसयू-30 ऑल-वेदर मल्टीरोल विमान हैं जबकि चीन का केवल जे-10 ही ऐसी योग्यता रखता है। मिराज-2000, मिग-29, सी-17 ग्लोबमास्टर मालवाहक विमान, सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमान के अलावा सुखोई-30 जैसे लड़ाकू विमान करीब चौने चार घंटे तक हवा में रहने और तीन हजार किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम हैं। इनके अलावा चिनूक और अपाचे जैसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर भी चीन से जंग में उस पर भारी पड़ेंगे। भारत की शक्तिशाली मिसाइल ब्रह्मोस भी युद्ध का नक्शा बदलने में मददगार हो सकती है, जिसकी रफ्तार 952 मीटर प्रति सैकेंड है और दुश्मन के रडार भी इसके सामने फेल हो जाते हैं। रखा विशेषज्ञों के मुताबिक यदि 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के रडार इसका पता लगा भी लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 30 सैकेंड से कम समय में इसे रोक पाना असंभव हो जाता है। आज का भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि चीन को इसके साथ सीधी जंग का फैसला करने से पहले सौ बार सोचने पर विवश होना पड़ेगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

## हिंदी दिवस या अंग्रेजी हटाओ दिवस?

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

भारत सरकार को हिंदी दिवस मनाते-मनाते 70 साल हो गए लेकिन कोई हमें बताए कि सरकारी कामकाज या जन-जीवन में हिंदी क्या एक कदम भी आगे बढ़ी? इसका मूल कारण यह है कि हमारे नेता नौकरशाहों के नौकर हैं। भारत के नौकरशाह हमारे स्थायी शासक हैं। उनकी भाषा अंग्रेजी है। देश के कानून अंग्रेजी में बनते हैं, अदालतें अपने फैसले अंग्रेजी में देती हैं, ऊंची पढ़ाई और शोध अंग्रेजी में होते हैं, अंग्रेजी के बिना आपको कोई ऊंची नौकरी नहीं मिल सकती। क्या हम अपने नेताओं और सरकार से आशा करें कि हिंदी-दिवस पर अंग्रेजी के सार्वजनिक प्रयोग पर वे प्रतिबंध लगाएंगे? यह सरहनीय है कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषाओं के माध्यम को लागू किया जाएगा लेकिन उच्चतम स्तरों से जबतक अंग्रेजी को विदा नहीं किया जाएगा, हिंदी की हैसियत नौकरानी की ही बनी रहेगी।

हिंदी-दिवस को सार्थक बनाने के लिए अंग्रेजी के सार्वजनिक प्रयोग पर प्रतिबंध की जरूरत क्यों है? इसलिए नहीं कि हमें अंग्रेजी से नफरत है। कोई मूर्ख ही होगा जो किसी विदेशी भाषा या अंग्रेजी से नफरत करेगा। कोई स्वेच्छा से जितनी भी विदेशी भाषाएं पढ़ें, उतना ही अच्छा! मैंने अंग्रेजी के अलावा रूसी, जर्मन और फारसी पढ़ी लेकिन अपना अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पीएचडी का

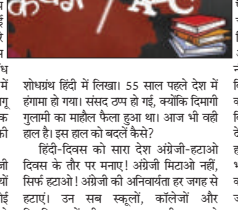


शोधग्रंथ हिंदी में लिखा। 55 साल पहले देश में हंगामा हो गया। संसद ठप्प हो गई, क्योंकि दिमागी गुलामी का माहौल फैला हुआ था। आज भी वही हाल है। इस हाल को बदलें कैसे?

हिंदी-दिवस को सारा देश अंग्रेजी-हटाओ दिवस के तौर पर मनाए! अंग्रेजी मिटाओ नहीं, सिर्फ हटाओ! अंग्रेजी की अनिवार्यता हर जगह से हटाएं। उन सब स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की मान्यता खत्म की जाए, जो अंग्रेजी माध्यम से कोई भी विषय पढ़ाते हैं। संसद और विधानसभाओं में जो भी अंग्रेजी बोले, उसे कम से कम छह माह के लिए मुअत्तिल किया जाए। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह महात्मा गांधी ने कहा था। सारे कानून हिंदी और लोकभाषाओं में बनें और अदालती बहस और फैसले भी उन्हीं भाषाओं में हों। अंग्रेजी के टीवी चैनल और दैनिक अखबारों पर प्रतिबंध हो। विदेशियों के लिए केवल एक चैनल और एक अखबार विदेशी भाषा में हो सकता है। किसी भी नौकरी के लिए अंग्रेजी अनिवार्य न हो। हर विश्वविद्यालय में दुनिया की प्रमुख विदेशी भाषाओं को सिखाने का प्रबंध हो ताकि हमारे लोग कूटनीति, विदेश व्यापार और शोध के मामले में पारंगत हों। देश का हर नागरिक प्रतिज्ञा करे कि वह अपने हस्ताक्षर स्वभाषा या हिंदी में करेगा तथा एक अन्य भारतीय भाषा जरुर सीखेगा। हम अपना रोजमर्रा का कामकाज हिंदी या स्वभाषाओं में करें। भारत में जब तक अंग्रेजी का बोलबाला रहेगा याने अंग्रेजी महारानी बनी रहेगी तबतक आपकी हिंदी नौकरानी ही बनी रहेगी।

## चाणक्य नीति

लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है। पर निंदा से बड़ा पाप क्या है। जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है। यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है। यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरुरत है। यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या जरुरत है और यदि अपमान हुआ है तो मृत्यु से भयंकर नहीं है क्या।

**काम की बात**

वही जीवित है जिसका मस्तिष्क ठंडा, रक्त गरम, हृदय कोमल और पुरूषार्थ प्रखर है।

**एक सलाह**

परवाह, आदर और थोड़ा समय, यही वह दौलत है, जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं।

# अपनी भाषा में हो शिक्षा और ज्ञान की साधना

गिरीश्वर मिश्र

भाषा संवाद में जन्म लेती है और उसी में पल-बढ़कर समाज में संवाद को रूप से संभव बनाती है। संवाद के बिना समाज भी नहीं बन सकता न उसका काम चल सकता है इसलिए समाज भाषा को जीवित रखने की व्यवस्था भी करता है। इस क्रम में भाषा का शिक्षा के साथ गहरा सरोकार बन जाता है। शिक्षा पाने के दौरान बच्चा भाषा भी सीखता है और भाषा के सहारे विभिन्न विषयों का ज्ञान भी प्राप्त करता है। उसकी योग्यता, कौशल और मानसिकता के विकास पर उसके आसपास फैली-पसरी भाषा की दुनिया का बड़ा व्यापक असर पड़ता है। भाषा के सहारे ही सोचना होता है और हम जीवन का गुणा-भाग लगाते हैं। रिश्ते-नातों का बनना बिगड़ना, मन ही मन वर्तमान, अतीत और भविष्य की काल-यात्रा करना, निर्णय लेना और अपनी हालत समझना और दूसरों को समझाना आदि सारे कार्य भाषा में दक्षता आने पर ही हो पाते हैं।

इस तरह भाषा पकड़ में आने के साथ बच्चे को अपने ऊपर और अपने परिवेश पर नियंत्रण का अहसास होने लगता है। भाषा से मिलने वाली शक्ति को आत्मसात करते हुए उसके साथ अस्मिता भी जुड़ जाती है और यदि समाज में कई भाषाएं हों तो उनकी आपस में प्रतिद्वंदिता होने लगती है और जो भाषा अधिक सक्षम होती है उसका आकर्षण उतना अधिक होता है। इस ढंग से कुछ भाषाएं दौड़ में आगे निकल जाती हैं और कुछ प्रयोग के अभाव में असहाय होकर अस्त होने लगती हैं। अनुमान है कि दुनिया में बोली जानेवाली लगभग छह हजार भाषाओं में से इस सदी के अंत होते न होते शायद मात्र 200 भाषाएं ही जीवित रहेंगी और शेष नष्ट हो जाएंगी। भारत की भाषाओं का भी इसमें बड़ा हिस्सा होगा। खासतौर पर लिपिहीन भाषाओं पर संकट ज्यादा गहरा है परंतु बड़ी जनसंख्या में प्रचलित भाषाओं की भी हालत विचारणीय है।

भाषा की सत्ता का लोकतंत्र की व्यवस्था, राष्ट्र की कल्पना और सांस्कृतिक जीवन्तता से अभिन्न रिश्ता है। भाषाओं का जाना संस्कृति और सभ्यता के लिए भी खतरे की घंटी है। भाषा भावनात्मक, सौंदर्य, सुरुचि और संस्कार का मार्ग प्रशस्त करती है। ज्ञान के निर्माण, प्रशासन, शिक्षा और अनुसंधान सबकी साधन होती है, उसकी भूमिकाओं के साथ भाषा की सापेक्षिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। भाषा को गम्भीर कार्य सौंपने पर उसकी मांग बढ़ती है। भारत में आज अंग्रेजी का आकर्षण खूब बढ़ा है और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तेजी से बढ़ते रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रति मोह की मनोवृत्ति, अंग्रेजियत की जीवनशैली और संस्कृति के विस्मरण की प्रवृत्ति ने सभ्यता का संकट खड़ा कर दिया है। चूंकि भाषा का कौशल समाज में रहते हुए ही अर्जित होता है इसलिए उसके निर्माण में सामाजिक परिवेश की खास भूमिका होती है। बोलने वाले की भाषा और उसके संवादी की भाषा में संगति और तारतम्य भी जरूरी होता है। इसलिए नई शिक्षा नीति की भाषा दृष्टि पर विचार करना जरूरी है।

शिक्षा नीति-2020 में भारतीय भाषाओं को लेकर जो विचार दिए गए हैं उनसे कुछ आशा बंधती है। यह संतोष की बात है कि यह नीति औपचारिक दुनिया में भारतीय भाषाओं के प्रति उदासीनता और इस कारण उनके अस्तित्व पर आ रहे संकट को रेखांकित करती है। भाषा द्वारा व्यक्ति और समाज की चेतना के निर्माण के महत्व को देखते हुए यह नीति इस बात को स्वीकार करती है कि भाषा का सवाल केवल शिक्षण माध्यम और विषय तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ शिक्षा के मूल सरोकार, राष्ट्रीय एकता, अवसरों की समानता, संस्कृति के पोषण और आर्थिक विकास के प्रश्न भी गुंथे हुए हैं। अतएव भाषा के बारे में फैसला सिर्फ बहुमत के आधार या प्रयोग की सुलभता के आधार पर नहीं लिया जा सकता। उसमें विविधता और समावेशन का पूरा स्थान होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में भाषा की उपस्थिति को भाषा-शिक्षण, शिक्षा के माध्यम के रूप में, भाषा को अध्ययन विषय के रूप में और भाषा के सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदना की दृष्टि से समझा जा सकता है। इस नीति के अनुसार भारतीय भाषाएं पूर्व विद्यालयी स्तर से लेकर शोध के स्तर तक औपचारिक शिक्षा का माध्यम बननी चाहिए। साथ ही भाषाओं को केवल उनके साहित्य तक सीमित न रख इतिहास, कला, संस्कृति तथा विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाने का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इस तरह भाषा के समुचित प्रयोग द्वारा समाज को लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया जा सकता है।

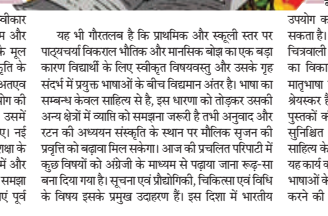

यह भी गौरतलब है कि प्राथमिक और स्कूली स्तर पर पाठ्यचर्या विकराल भौतिक और मानसिक बोझ का एक बड़ा कारण विद्यार्थी के लिए स्वीकृत विषयवस्तु और उसके गृह संदर्भ में प्रयुक्त भाषाओं के बीच विद्यमान अंतर है। भाषा का सम्बन्ध केवल साहित्य से है, इस धारणा को तोड़कर उसकी अन्य क्षेत्रों में व्याप्ति को समझना जरूरी है तभी अनुवाद और रटन की अध्ययन संस्कृति के स्थान पर मौलिक सृजन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकेगा। आज की प्रचलित परिपाटी में कुछ विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जाना रूढ़-सा बना दिया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा एवं विधि के विषय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस दिशा में भारतीय भाषाओं के माध्यम से पहल होनी चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि कला, शिल्प, खेल और देशज ज्ञान को अपनी भाषा के माध्यम से ही खोजा और संरक्षित किया जा सकता है। नीति का यह मानना है कि ज्ञान, विज्ञान और कौशल की दृष्टि से भाषाओं को रोजगार की दुनिया में स्थापित किया जाना चाहिए। नीति में प्राचीन भाषाओं के लिए आदरभाव विकसित करने और भाषा शिक्षकों की नियुक्ति को प्रोत्साहन देने का सुझाव स्वागत योग्य है। सूचना क्रान्ति को अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त करते हुए भारतीय भाषाओं के माध्यम को सार्थक बनाने हेतु भारतीय भाषाओं के शिक्षण को समर्थ बनाने के लिए विचार करना होगा। भारतीय भाषाएं इतनी समर्थ हैं कि इनके द्वारा ज्ञान का सृजन और स्थानान्तरण किया जा सकता है। साथ ही औपचारिक शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं अन्य सामाजिक-राजनीतिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग सुगमतापूर्वक किया जा सकता है।

जहां तक पूर्व विद्यालयी शिक्षा का प्रश्न है, मातृभाषा का प्रयोग करते हुए सोचने-विचारने की प्रक्रिया का सूत्रपात करना ही सर्वथा हितकर होगा। बच्चे की भाषा सीखने की सहजात क्षमता का उपयोग करते हुए सीखने का सक्रिय परिवेश बनाया जा सकता है। बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए चित्रवाली किताबों एवं अन्य भाषा शिक्षण सहायक सामग्री का विकास करना आवश्यक होगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण को अनिवार्यतः लागू किया जाना ही श्रेयस्कर है। इस हेतु गणित, विज्ञान आदि विषयों में रोचक पुस्तकों की रचना एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा। भारतीय भाषाओं में बालोपयोगी साहित्य के लिए राष्ट्रीय मिशन को संचालित कर युद्धस्तर पर यह कार्य करना होगा। नीति में तो उच्च शिक्षा तक को भारतीय भाषाओं के माध्यम से संचालित करने के अवसर का विस्तार करने की संस्तुति की गई है। यह सर्वविदित है कि चीनी, जापानी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, हिब्रू आदि गैरअंग्रेजी भाषा माध्यम में उच्चतम स्तर की शिक्षा दी जा रही है और शोध किया जा रहा है। अतः भारतीय भाषाओं में भी उच्चस्तरीय शोध होना चाहिए। नई शिक्षा नीति कला, शिल्प, इतिहास, देशज विज्ञान और लोक विद्या को भी औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाने को सोच रही है। इनमें प्रवेश के लिए अपनी भाषा ही उपयुक्त होगी। भारतीय भाषाओं को व्यावसायिक शिक्षा में यथोचित स्थान देते हुए रोजगार बाजार से जोड़ना होगा।

आज सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में भाषायी कौशलों का संवर्धन बड़ी चुनौती हो गई है। आज की सबसे बड़ी सीमा है कि विद्यार्थी लिखित और मौखिक रूप में ठीक से संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। अतः भाषायी दक्षता का संवर्धन जरूरी है। चूंकि सहज संज्ञानात्मक सक्रियता मातृभाषा में होती है अतरू भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तक और अन्य पुस्तकों की उपलब्धता और उन्हें सतत अद्यतन करते रहना आवश्यक होगा। भारतीय भाषाओं में पारस्परिक संबंध विद्यमान है। कई क्षेत्रीय बोलियां जो लगभग भाषा जैसी है उनमें शब्दों, संज्ञाओं आदि की समानता का लाभ लेना होगा। अध्यापकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण में उनकी भाषा संबंधी योग्यताओं में सुधार एवं परिष्कार जरूरी होगा।

अपनी भाषा को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का आधार बनाने की बात पुरानी है। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो आज से डेढ़ सौ साल पहले ऐसा ही उद्घोष किया था। 'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति की मूल। तासों सब मिल छाड़ि के दूजे और उपाय उन्नति भाषा की करौ अहै भ्रात गण भाय।' अब तक बने आयोगों और समितियों ने भी बात दुहराई थी पर उसे कार्य रूप देने का मुहूर्त अब आ रहा है। देर से सही अपनी भाषा में शिक्षा की पहल दुरुस्त कदम है।

(लेखक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विवि, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

# नई शिक्षा नीति से समर्थ भारत का सपना होगा साकार

भारतीय शिक्षा के मूल में संस्कार,अन्तर्निहित शक्तियों का विकास,कौशल विकास तथा नैतिकता के भाव निहित है,इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना होता है। भारतीय शिक्षा के भाव में सनातनकाल से मानवता के महान आदर्श,मूल्य और सार्वभौमिकता की उच्च कोटि की भावना विद्यमान रही है। आजादी के बाद देश में सामाजिक न्याय स्थापित करने के उद्देश्य में व्यापक सफलता न मिल पाने का मूल कारण शिक्षा प्रणाली को लेकर भटकाव तथा दीर्घकालीन और व्यापक योजनाओं का अभाव रहा है।

आजादी के बाद से ही हमारे देश में ऐसी शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिससे हमारी भावी पीढ़ी विज्ञान के साथ भारतीय आदर्शों और मूल्यों से भी जुड़े। यह विश्वास किया जाता है कि जो लोग एक वर्ष का सोचते हैं, वह अनाज बोते हैं, जो दस वर्ष का सोचते हैं, वो फलों के वृक्ष बोते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। मतलब उसको शिक्षित करना,संस्कारित करना तथा उसके जीवन को तैयार करना। नई शिक्षा नीति एक व्यापक उत्कृष्ट योजना है जो समर्थ भारत के निर्माण की व्यापक संभावनाएं जगाती है।

आजादी के आठवें दशक में हम प्रवेश कर चुके है और इस समय देश के सामने असंख्य चुनौतियां है। इसका सबसे प्रमुख कारण अधिकांश पूर्व की सरकारों की ऐसी नीतियाँ भी रही है जिसके कारण समर्थ भारत बनने में कठिनाई उत्पन्न हुई है। नई शिक्षा नीति ऐसी चुनौतियों को खत्म कर समर्थ भारत बनाने की ऐसी परिकल्पना है,जिसे हम सब मिलकर साकार कर सकते है। 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, इसके 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है। शिक्षा देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसकी जरूरत को देखते हुए जीडीपी का छह फीसदी शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है जो फिलहाल अपेक्षाकृत कम है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

नई शिक्षा नीति बाल अवस्था से ही नैतिक,शारीरिक और बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके साथ ही देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए देश की एकता और अखंडता को भी मजबूत करती है। इसमें पाँचवी क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य बालपन से ही भारतीयता के मूल स्वभाव के अनुरूप विद्यार्थी का आचरण और व्यवहार की शिक्षा देना है जिससे उनमें ज्ञान के साथ के लिए इस बात की जरूरत है कि स्कूल से ड्रॉप आउट को खत्म किया जाये। नई शिक्षा नीति में 2030 तक माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अभी स्कूल से दूर रह रहे दो करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। संस्थात्मक दृष्टि से बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा,इसमें 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करने की व्यापक योजना है। सामाजिकता का यथोचित विकास होने की संभावनाएं बलवती हो। देश में सौ फीसदी उच्च शिक्षित समाज के लक्ष्य पर काम करने स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं,पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच अंतर नहीं किए जाने पर जोर दिया गया है,जिससे विद्यार्थी ज्ञान के साथ कौशल विकास की ओर प्रवृत हो सके।

देश में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समावेशी विकास की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता के अनुसार प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक साल 2022 तक विकसित किया जाएगा।

डॉ.मोहन यादव

प्रत्येक माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों को उच्च शिक्षा मिले और नई शिक्षा नीति इसका मार्ग प्रशस्त करती है। उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 2035 तक 50 फीसदी तक पंजीयन का लक्ष्य है जबकि फिलहाल यह महज 26.3 प्रतिशत ही है। इसके लिए उच्च शिक्षा में साढ़े तीन करोड़ नई सीटें बढाई जाएगी। इसे व्यापक,रचनात्मक और बहुआयामी बनाया गया है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आजादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरे कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। शोध को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र शोध करना चाहते हैं उनके लिए चार साल का डिग्री प्रोग्राम होगा जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो तीन साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। शोध करने के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा।

शिक्षा समर्थ व्यक्ति,समर्थ समाज और समर्थ राष्ट्र बनाती है। बेहतर शिक्षा से स्वर्णिम भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृतसंकल्पित है और इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश सभी क्षेत्रों में प्रगति के सोपान छू रहा है और हम सब नई शिक्षा नीति से समर्थ भारत का सपना साकार करने के लिए कृतसंकल्पित होकर आगे बढ़ रहे है।

(लेखक मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है)

# कितने किस्म के हिन्दू!

के.विक्रम राव

पितृपक्ष चल रहा है। सत्रह सितम्बर (बृहस्पतिवार) को श्राद्ध का अंतिम दिन रहेगा। गंगाजमुनी हिन्दू इस प्रथा का उपहास करते हैं। छद्म आस्थावान छिपे-सहमे रीति से परिपाटी निभाएंगे। कई श्रद्धालु एक दफा जीवन में गया-तीर्थ जाने के बाद निवट जाते हैं। किन्तु बहुतायत में अन्य जन सारी रस्में मन से निभाते हैं। इसी आखिरी समूह का तरीका मुझे बहुत भाता है।

पुरखों का आदर मरणोपरांत भी करना यह दर्शाता है कि नयी पीढ़ी कृतघ्न नहीं है। ऐसे मृत्यु के पश्चात वाले आचरण हमें सुर्योपासक पारसियों, ख्रिस्तीजन, जैन तथा बौद्धों से सीखना चाहिए। वे अपने सभी निर्देशित रस्मों का विधि-विधान के अनुसार निर्वहन करते हैं। अर्थात पुण्यकर्म से लाज, हिचक क्यों?

यहाँ चौथे मुगल बादशाह शाहबुद्दीन मुहम्मद शाहजहाँ (खुर्रम) की उक्ति का जिक्र कर दूं। श्राद्ध पद्धति का उल्लेख अतीव व्यथा से शाहजहाँ ने किया था। अपने बेटे औरंगजेब आलमगीर से बादशाह ने कहा, 'हिन्दुओं से सीखो। वे अपने मरे हुए वालिद (पिता) को भी तर्पण में पानी पिलाते हैं और तुम हो कि अपने जीवित पिता को टूटे घड़े में आधा भरकर ही पानी देते हो, प्यासा रखते हो !' बाप से बेटे ने गद्दी हथियाते ही आगरा के किले में बादशाह को कैद कर रखा था। मसलन पारंपरिक रिश्ते निभाने में हिन्दू को शहंशाह ने बहुत बेहतर बताया था।

आर्यसमाजी भी हिन्दुओं में होते हैं जो मूर्ति-भंजक (इस्लामिस्टों की भांति बुतशिकन) हैं। वे श्राद्ध का बहिष्कार करते हैं। हालाँकि वे वेदोक्त रीतियों को तो मानते हैं। मगर यह नही स्वीकारते कि अथर्ववेद (18-2-49) में उल्लिखित है कि पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए: 'येनः पितुरू पितरो ये पितामहा तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम।' हिन्दू संप्रदाय के समाजशास्त्रीय प्रबंधन हेतु यह प्रथाएं रची गई थीं। किन्तु नौ सदियों तक के इस्लामी राज में नगरीय क्षेत्रों से ये परम्पराएँ लुप्तप्राय हो गयी हैं। आंचलिक क्षेत्रों में दिखती हैं।

पिण्डदान के विषय में कई भारतीयों के भ्रम को दूर करने हेतु मैं लन्दन के एक महान वैज्ञानिक का अनुभव बता दूं। चूँकि वह गोरा अंग्रेज था तो हम गेहुंए भारतीय, युगों से दासता से ग्रसित रहे, तो शायद विचार करलें और मान भी लें कि आत्माएं होती हैं और विचरण करती रहती हैं। उनसे संवाद संभव है। आत्मिक सुधार हेतु सहायता भी।

इसी सन्दर्भ में लखनऊ विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी विभाग के हमारे एक साथी ने कभी (1959) एक लेख का उल्लेख किया जिसे ब्रिटेन के महान भौतिक शास्त्री लार्ड जॉन विलियम्स स्ट्रट रेले ने लिखा था। जॉन विलियम्स को 1904 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे बड़े धर्मनिष्ठ थे और परामिज्ञान में निष्णात थे। प्लैशेट पर वे बहुधा अपने दिवंगत इकलौते पुत्र से संवाद करते थे।

एक बार पुत्र ने उन्हें बताया कि वह एक अत्यंत ज्वलनशील स्थान पर है। मगर भारतीय आत्माएं यहाँ से शीघ्र मुक्ति पा लेती थीं क्योंकि उनके भूलोकवासी रिश्तेदार आटे से गेंदनुमा ग्रास बनाकर कोई रस्म अदा करते थे। अर्थात पिंडदान ही रहा होगा। अतः अब श्राद्ध प्रथा में यकीन करना होगा।

# अपने लड़ाकू स्वभाव को स्वीकार करो

मैं योद्धा हूं। मुझे युद्ध के सिवाय कुछ नहीं आता। और खराब बात यह है कि मुझे वह अच्छा लगता था। भयंकर तृष्णा के सम्मुख खडा होकर ठहाका मारना मुझे प्यारा लगता है। सूरज की धूप में लेटकर पिघलना मुझे नहीं भाता।

उसमें कोई समस्या नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम योद्धा हो, तुम्हें युद्ध में मजा आता है ,इतना ही नहीं, तुम्हें योद्धा होने पर गर्व है तो निश्चिन्त हो जाओ। समग्रता से लड़ो। अपनी लड़ाकू वृत्ति से मत लड़ो। तुम्हारे लिए यही लेट गो, यानी स्वीकार भाव होगा। भयंकर तृष्णा के आगे खड़े होकर हंसना बिलकुल ठीक है, इसमें अपराध बोध को मत पालो। सिर्फएक बात समझने की कोशिश करोरू जब मैं कहता हूं लेट गो, मेरा यह मतलब नहीं है कि तुम्हें कुछ बदलना है। मेरा इतना ही मतलब है कि तुम जो भी हो उसकी समग्रता को प्रगट होने दो।

अपने पूरे अंतरतम के साथ लड़ाकू बनो। और इस समग्रता में तुम पाओगे कि तुम्हारा हृदय पिघल रहा है। यह तुम्हारे समग्र होने का पुरस्कार है। उसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, पुरस्कार अपने आप आते हैं। सिर्फऊस कृत्य में समग्र हो जाओ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें पसंद है, जिस पर तुम्हें गर्व हैय उसमें समग्र हो जाओ। कोई दरार मत बनाओ। आधे-आधे मत रहेय आंशिक मत रहो। अगर तुम समग्र हो तो एक दिन तो बड़े से बड़े तूफान के आगे हंसते हुए तुम पाओगे कि धूप में तुम्हारा हृदय पिघल रहा है। वह तुम्हारे लिए एक पुरस्कार की तरह आएगा।

आदमी बिना वजह समस्याएं पैदा करता है। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जीवन में कोई समस्याएं नहीं हैं सिवाय उनके जो तुम पैदा करते हो। उन्हें देखने की कोशिश करोरू तुम्हें जो भी अच्छा लगता है वह अच्छा है। और तुम समग्र हो कि नहीं यह तो पुरस्कार से ही तय होगा। कभी तुम्हें अचानक पिघलने का भाव हो तो तुम जानोगे कि तुमने खुद को धोखा नहीं दिया हैय कि तुम ईमानदार और सच्चे थेय और कि अब वस्तुतरू वह बिंदु आ गया जब तुम गर्व अनुभव करोगे।

# भारतीय लोकतंत्र पर आपराधीकरण हावी...!

आज से करीब साढ़े छः वर्ष पूर्व हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने अपने पहले संसदीय भाषण में वादा किया था कि देश में जितने भी मौजूदा व पूर्व संसदों व विधायकों पर न्यायालयों में आपराधिक प्रकरण चल रहे है उनका निपटारा विशेष न्यायालयों का गठन कर एक वर्ष में कर दिया जाएगा और देश की सियासत को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा, पचहत्तर महीनें बाद भी मोदी जी अपनी इस पहले संकल्प को मूर्तरूप नहीं दे पाए, हमारे प्रधानमंत्री की तो पूरे विश्व में ''एक सशक्त प्रधानमंत्री'' की पहचान है और पूरा विश्व इस पहचान का सम्मान भी करता है, फिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री चाहते हुए भी अपने पहले संकल्प को मूर्तरूप नहीं दे पाए और आज देश भर के उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय को लिखकर देना पड़ रहा है कि आज भी देश के मौजूदा पूर्व व वर्तमान सांसदों-विधायकों पर करीब साढ़े चार हजार (4442) आपराधिक प्रकरण लम्बित है, इनमें से आधे से अधिक (2556) आपराधिक प्रकरण मौजूदा सांसदों-विधायकों पर लम्बित है। क्या उच्च न्यायालयों की इस खुली रिपोर्ट से हमारा प्रजातंत्र कलंकित नहीं होता? और यदि अभी कुछ वर्ष और यही चलता रहा तो फिर क्या यह लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा?

शायद इसी कारण हमारे निर्वाचित जन प्रतिनिधि जिनके बारे में संवैधानिक धारणा एक जनसेवक की है, उनसे वे ही लोग हमेशा भयभीत रहते है, जिनके मतों से ये आपराधिक तत्व राजनीति में रूतबें के सिंहासन तक पहुंचे, इस मामले में प्रजातंत्र का हर स्तंभ डरा-सहमा सा है, क्योंकि इनका सतत् प्रयास हर स्तंभ पर कब्जा करना हो गया है, विधायिका के तो ये सदस्य है ही, कार्यपालिका इनके नियंत्रण में रहती है और सिर्फ न्यायपालिका ही है, जिस पर इनका जोर नही चल पाता, इसलिए तीनों स्तंभों में न्यायपालिका पर ही देश की जनता का भरोसा रह गया है और चौथे अघोषित स्तंभ खबर पालिका की तो बात ही नहीं करें, वह तो स्वयं इन आपराधिक जन प्रतिनिधियों के नियंत्रण में रहने को उत्सुक है।

कुल मिलाकर आज-कल प्रजातंत्र की मुख्य धुरी चुनाव भी तमाशा बनकर रह गए है, आज चुनाव किस तरह जीते जाते है, यह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, आपराधिक तत्वों के प्रति चुनाव आयोग न तो सख्ती कर पाता है और न उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित ही कर पाता है, इसलिए ऐसे तत्व भय व डर के बल पर चुनाव जीतकर हमारे पवित्र प्रजातंत्र के मंदिरों (संसद-विधानसभा) में पहुंच जाते है और अपनी हर महत्वाकांक्षा की पूर्ति उसी हैसियत का दुरूपयोग कर करते है, फिर वह चाहे धनोपार्जन हो या रूतबा।

आज हमारी आजादी को तिहत्तर साल होने आए और संविधान को लागू हुए 70 साल से अधिक हो गए और हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से हमारे प्रजातंत्र के इन मंदिरों को अपराध और आपराधिक तत्वों से दूर रखने का उल्लेख है, किंतु इसके बावजूद क्या कारण है कि हमारा चुनाव आयोग स्वयं ही संविधान की भावना का सम्मान नहीं कर पा रहा है, क्या चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संगठन पर भी सत्ता के सिंहासनों पर विराजित ये तत्व हावी हो गए है? इसी एक कारण से हमारे प्रजातंत्र की छवि पूरे विश्व में कितनी खराब हो रही है? इसकी तनिक भी चिंता हमारे इन कलयुगी भाग्यविधाताओं को है? चुनाव आयोग हर चुनाव के पहले राजनीतिक दलों का इस बारे में आगाह करता रहता है, किंतु राजनीतिक दलों पर उसका कोई असर नहीं होता। अब तो सर्वोच्च न्यायालय को ही कुछ करना पड़ेगा तथा चुनाव आयोग के नियमों के साथ यह जोड़ना पड़ेगा कि जिन प्रत्याशियों के यदि किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित है तो उसे चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए, जब तक वह सभी प्रकरणों में निर्दोष साबित न हो जाए तब तक वह पंचायत से लेकर संसद तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, अब समूचे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर ही केन्द्रित है, जिसने पूरे देश के उच्च न्यायालयों से यह रिपोर्ट प्राप्त की है, साथ ही स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी अपनी प्राथमिकताओं में अपने इस संकल्प को मूर्तरूप देने वाले इस पुनीत कार्य को शामिल करना चाहिए, जिससे कि अन्य मुद्दों के साथ प्रजातंत्र की अस्मिता से जुड़ा यह मामला भी सुलझ सके और उनकी पहली संकल्पित घोषणा को मूर्तरूप मिल सके।

ओमप्रकाश मेहता लेखक

# राफेलः एक नजर इधर भी

भारत चीन के बीच चल रही जबरदस्त तना तनी के बीच फ्रांस निर्मित बहुचर्चित एवं विवादित युद्धक विमान 'राफेल' गत 10 सितम्बर को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। इस अवसर पर अम्बाला छावनी स्थित वायुसेना स्टेशन पर एक समारोह आयोजित हुआ जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,उनकी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ले व सेना व वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले जब राफेल ने 29 जुलाई 20 को भारत की धरती पर अंबाला एयर फोर्स स्टेशन के रनवे पर अपनी सबसे पहली लैंडिंग की थी उस समय भी इन युद्धक विमानों का जोरदार स्वागत किया गया था। राफेल को 'वॉटर सेल्यूट' देते हुए दोनों ओर से फायर ब्रिगेड के रथे के बीच से निकाला गया था। पूजा पाठ व राफेल को बुरी नजर से बचाने का सिलसिला तो फ्रांस से लेकर अंबाला तक रखा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बल्कि उन्हीं के 'पावन' हाथों से होता आया है। नींबू-मिर्च व नजर उतारने के सभी 'उपाय' भी किये जा चुके हैं। रक्षा मंत्री ने 'हैप्पी लैंडिंग इन अंबाला' का सन्देश देकर राफेल का स्वागत किया था। गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा फ्रांस सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद का सौदा लगभग 59,000 करोड़ रुपये में किया गया है। इन्हें 36 राफेल फाइटर विमानों में से मात्र 5 विमानों का पहला बैच फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से उड़कर संयुक्त अरब अमीरात होता हुआ अंबाला पहुंचा है और उन्हें 5 विमानों की शान में 29 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक के यह सभी समारोह आयोजित होते रहे हैं। खबर है कि दिसंबर 2021 तक संभवतः सभी 36 राफेल विमान भारत पहुँच जाएंगे।

29 जुलाई को जिस दिन 5 राफेल की आमद हो रही थी उस दिन का मीडिया कवरेज तथा अम्बाला वायुसेना स्टेशन के आस पास के सुरक्षा प्रबंध देखने लायक थे। अम्बाला वायु सेना क्षेत्र में प्रवेश निषेध होने के बावजूद मीडिया बता व दिखा रहा था कि किस समय 5 राफेल की टुकड़ी ने भारतीय आकाश में प्रवेश किया और आकाश में ही भारतीय वायु सेना के दो सुखोई फाइटर विमानों ने उनकी अगवानी की। अरब सागर में तैनात भारतीय नव सेना के युद्ध पोत आईएनएस कोलकाता द्वारा भी भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर राफेल का स्वागत किया गया। 29 जुलाई को मीडिया के लगातार प्रसारण ने विशेषकर अंबाला में कुछ ऐसा माहौल बना दिया था कि हजारों लोग तेज धूप के बावजूद अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर वायु सेना के इस नए मेहमान के दर्शन करने को बेचैन दिखाई दिए। कुछ स्थानीय अखबारों ने उस दिन 'अम्बाला में आज दीवाली' जैसे शीर्षक लगाकर राफेल के आने की खबर प्रकाशित की थी। 29 जुलाई को राफेल की सुरक्षा के दृष्टिगत अंबाला जिला प्रशासन द्वारा एयर फोर्स स्टेशन के तीन किलोमीटर परिक्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रशासन हाई एलर्ट पर था तथा राफेल लैंडिंग के दौरान छतों से फोटोग्राफी करना व लोगों का जमावड़ा लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। पक्षी उड़ाने व पतंगबाजी करने तक पर रोक थी। जाहिर है यह सभी एहतियाती उपाय इसीलिये किये जा रहे थे ताकि बेशकीमती राफेल की सुरक्षा में कोई चूक या कमी न रह जाने पाए।

राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से पूर्व भी अंबाला वायु सेना स्टेशन मिग-21 व जगुआर जैसे युद्धक विमानों का केंद्र रहा है। देश के पश्चिम क्षेत्र की महत्वपूर्ण निगरानी केंद्र होने के कारण यहाँ दशकों से मिग-21 व जगुआर प्रायः अपनी नियमित उड़ानें भरते रहते हैं। कम से कम ऊंचाई पर भी उड़ने की क्षमता रखने वाले इन विमानों की सुरक्षित उड़ान के मद्देनजर ही इस हवाई क्षेत्र के आसपास के इलाके में तीन मंजिला इमारत बनाए जाने पर कानूनन रोक है। परन्तु इसी शहर में मोबाईल टावर्स की भरमार जरूर है। राफेल की भारी कीमत और चीन से चल रहे वर्तमान तनावपूर्ण हालात को देखते हुए न केवल समस्त भारतवासियों बल्कि सभी सरकारी व गैर सरकारी विभाग के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे राफेल की सुरक्षा सुनिश्चित करें और इस दिशा में अपना हर संभव योगदान भी दें। पिछले दिनों मैंने रात के समय अम्बाला के आस पास विशेषकर शहरी क्षेत्र का भ्रमण इसी मकसद से किया ताकि देख सकूं कि राफेल की आमद पर जश्न मनाने वाला देश आखिर राफेल की सुरक्षा के प्रति कितना गंभीर है। मैंने पाया कि 50 फुट से लेकर 200 फुट तक की ऊंचाई वाले अधिकांश मोबाईल टावर्स के शीर्ष का संकेत देने वाली लाल लाइट बुझी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि बी एस एन एल व रेलवे जैसे माइक्रोवेव टावर्स जो कि लगभग 350 से लेकर 500 फुट तक की ऊंचाई रखते हैं उनमें भी कई टावर्स के शीर्ष पर आवश्यक रूप से जलने वाली सकेत रुपी लाल बत्ती बुझी हुई थी। मिग हो या जगुआर या अब भारतीय वायु सेना में नया शामिल हुआ राफेल,जरुरत पड़ने पर या अपनी नियमित उड़ान के समय भी कभी कभी बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं।

राफेल की सुरक्षा के प्रति वायुसेना के अधिकारियों की भी चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गत 10 सितंबर को राफेल के औपचारिक रूप से वायुसेना के बड़े में विधिवत शामिल होने से पूर्व ही भारतीय वायु सेना के निरीक्षण और सुरक्षा महानिदेशक, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने, हरियाणा की मुख्य सचिव, केशनी आनंद अरोड़ा को एक आधिकारिक पत्र लिखकर अंबाला एयर फोर्स स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में कचरा निपटाने के लिए त्वरित उपाय करने का अनुरोध किया है। ऐसा पत्र कचरे के चलते पक्षी इकट्ठा होने व इनके उड़ने के कारण राफेल लड़ाकू विमान की सुरक्षा को होने वाले संभावित खतरे के दृष्टिगत लिखा गया है। गौरतलब है कि अंबाला वायुसेना क्षेत्र में पक्षियों की संख्या अधिक होने के कारण टकराव होने से इन बेशकीमती विमानों को बहुत गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

तनवीर जाफरी

वायु सेना ने स्थानीय शहरी निकाय विभाग से भी मांग की है कि कम से कम अम्बाला एयरफील्ड के आसपास 10 किलोमीटर की परिधि में पतंगों व बड़े पक्षियों की गति विधि को कम करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना (एसडब्ल्यूएम) को तत्काल कार्यान्वित किया जाए। वायु क्षेत्र से उपयुक्त दूरी पर उपयुक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) संबंधी प्लांट तत्काल स्थापित किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि वायुसेना द्वारा अंबाला वायु सेना स्टेशन के आसपास कबूतर प्रजनन गतिविधि को निषिद्ध व नियंत्रित करने के लिए भी प्रशासन से कहा गया है।

जाहिर है कि राफेल के शुभागमन मात्र से ही राफेल की जरुरत नहीं पूरी होने वाली बल्कि इसके रखरखाव की सबसे अहम जरुरत अर्थात इसकी पूर्ण सुरक्षा तथा इसके लिए निर्बाध हवाई रास्ता उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। लिहाजा केंद्र व राज्य सरकारों को आपसी ताल मेल से यथाशीघ्र इसकी सुरक्षा संबंधी सभी उपाय करने चाहिए। सभी ऊँचे टावर्स की लाल बत्ती रात के समय तत्काल जलनी चाहिए और हवाई क्षेत्र के आसपास से कूड़े के निपटान का काम व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना (एसडब्ल्यूएम) की स्थापना आदि जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।

## न्यूज ब्रीफ

### मुख्यमंत्री चौहान 19 सितम्बर को पुनासा में, विभिन्न निर्माण कार्यों का करेंगे भूमिपूजन व लोकार्पण

**माही की गूंज, खण्डवा।** प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 सितम्बर को खण्डवा जिले के पुनासा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री चौहान 19 सितम्बर को दोपहर 12:40 बजे भोपाल से हेलीकाप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर डेढ बजे पुनासा आयेंगे, तथा स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कार्यक्रम के दौरान 6 करोड 75 लाख रूपए के विकास कार्यो का भूमिपूजन और 9 करोड 12 लाख रूपए के कार्यो का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान अपरान्ह 3 बजे खकनार जिला बुरहानपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

### दो पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक मदद स्वीकृत

**माही की गूंज, खण्डवा।** राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा से जानमाल की हानि होने पर प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुविभागीय अधिकारी पंधाना सीएस सोलंकी ने बताया कि, शिवत पिता कैलाश निवासी ग्राम अस्तरिया एवं पृथ्वी पिता उमेश निवासी ग्राम बोरगांव बुजुर्ग की गत दिनों पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इन दोनों मृतक के परिवारों के निकटतम सदस्य को राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत 4-4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

### आईटीआई. तृतीय चयन सूची 18 सितम्बर को होगी जारी, 19 से 22 सितम्बर तक होगा प्रवेश

**माही की गूंज, खण्डवा।** आईटीआई प्रवेश में तृतीय चयन सूची 18 सितम्बर को जारी होगी। इसमें प्रवेश प्रक्रिया 19 सितम्बर से प्रारंभ होकर 22 सितम्बर तक पूर्ण कर ली जायेगी। डीएसटी के तहत प्रवेश के लिए मेरिट सूची के आवेदकों का साक्षात्कार, चयन तथा प्रवेश की प्रक्रिया 19 से 22 सितम्बर के मध्य की जायेगी। पोर्टल पर 24 सितम्बर को संस्थावार, श्रेणीवार रिक्त सीटों की जानकारी प्रदर्शित की जायेगी। रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग के लिए पोर्टल 25 सितम्बर को पुनः ओपन किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2020 में आईटीआई में अब तक कुल 11 हजार 390 बच्चों को प्रवेश दिया गया है। इसके तहत क्राॅस ट्रेनिंग स्किल में 11 हजार 68, इंडिस्ट्रीयल मेजमेंट समिति में 201 तथा डयूल सिस्टम ऑफ्ट्रेनिंग में 121 बच्चों को प्रवेश मिला है।

### मुख्यमंत्री आज जिले की दो ग्रामीण महिलाओं से करेंगे वीडियो काफ्रेंसिंग से चर्चा

**माही की गूंज, बड़वानी।** प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रातः साढ़े 11 बजे पोषण सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश स्तर से करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के 4 जिले बड़वानी के ग्राम पंचायत ओसाड़ के कुपोषित बच्चो की माताओं से, ग्वालियर के ग्राम पंचायत सिहोना एवं श्योपुर की ग्राम पंचायत पाण्डोला के भी कुपोषित बच्चो की माताओं से एवं डिण्डोरी जिले की तेजस्वी समूह की महिलाओं से चर्चा करेंगे।

कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि, 17 सितम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किए जा रहे पोषण सरकार कार्यक्रम के लिए विकासखण्ड पाटी के ग्राम पंचायत बुदी के पंचायत भवन में व्यवस्था की गई है। जहाँ से ओसाड़ की कुपोषित बच्चो की माताए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री से सीधी चर्चा करेंगी। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम देखने एवं सुनने की व्यवस्था जिले के सभी ग्राम पंचायतो में की गई है।

# आंगनवाड़ी भर्ती मामले में फिर हुई हेरा-फेरी, जांच और आपत्ती के नाम पर चल रहा तमाशा

## आपत्ती लगाने वाली महिला को छोड़, बिना आपत्ती वाली महिला की बिना जाती प्रमाण-पत्र के कर दी नियुक्ति

**माही की गूंज, पेटलावद (झाबुआ)।**

गूंज द्वारा आंगनवाड़ी भर्ती घोटाले के खुलासे के बाद अब जिले से जाँच में हेरा-फेरी का मामला सामने आया है । गूंज द्वारा पेटलावद विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बावडी के मातापाडा फलिए में हुई आंगनवाड़ी फ्ली भर्ती का खुलासा किया गया था, जिसमे पेटलावद की महिला को बावडी पंचायत का निवासी मानकर तुलनात्मक सूची में प्रथम स्थान दिया गया था, जिस पर दूसरे स्थान पर रही देवली पति मनीष गरवाल जो कि तुलनात्मक सूची में दूसरे स्थान पर रही, उसके द्वारा लिखित आपत्ति दर्ज करवाते हुए नियुक्ति को गलत बताकर स्वयं को पात्र बताया था। मामला जाँच में था, लेकिन तुलनात्मक सूची में प्रथम स्थान पर बताई गई महिला ने उक्त पद पर निजी कारणों से कार्य नही करने की सुचना लिखित में विभाग को दे दी, जिसके बाद दूसरे स्थान वाली आपत्तिकर्ता देवली गरवाल पूर्णतः आश्वस्त थी कि, भर्ती प्रक्रिया के नियमो के अनुसार प्रथम स्थान पर रही महिला यदि किसी वजह से अपात्र होती है तो दूसरे स्थान वाली अभ्यर्थी को मौका दिया जाता है।

### चौथे स्थान पर रही अभ्यर्थी के जारी कर दिए नियुक्ति आदेश

जिले में बैठे अधिकारियों ने जो आपत्ति पर जाँच कर रहे भर्ती नियमो को ताक में रख एक बार फिर पात्र व आपत्तिकर्ता अभ्यर्थी देवली गरवाल की नियुक्ति आदेश जारी नही करते हुए तुलनात्मक सूची में चौथे स्थान पर रही महिला निर्मला पति मुकेश की नियुक्ति कर दी, आपत्तिकर्ता महिला ने जब इसकी जानकारी महिला बाल विकास विभाग कार्यालय पेटलावद से निकाली तो जाँच दल ने चौथे स्थान पर रही महिला की नियुक्ति के लिए जाति प्रमाण-पत्र के दस नम्बर नही जोड़े जाने का तर्क देते हुए उसके दस नम्बर जोड़े गए, जिससे चौथे नंबर पर रही महिला के अंक अन्य सभी अभ्यार्थीयो से अधिक होने से उसकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए।

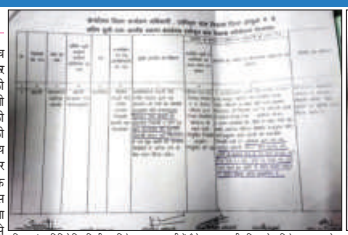

जिला जांच समिति ने बिना किसी आपत्ति के तुलनात्मक सूची में चौथे स्थान पर रही महिला को जाति के दस नम्बर जोड़ कर पात्र घोषित कर दिया।

महिला बाल विकास पेटलावद से सूचना अधिकार अधिनियम में प्राप्त जानकारी जिसमे नियुक्त निर्मला पति मुकेश द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नही ही गई।

### सूचना अधिकारी में यह हुआ खुलासा

चौथे स्थान पर रही महिला ने न आपत्ति दर्ज करवाई न ही आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र दिया, आपत्तिकर्ता देवली पति मुकेश की नियुक्ति नही होने पर आपत्तिकर्ता द्वारा विभाग से सूचना अधिकार अधिनियम में आवेदन देकर मातापाडा फलिए में आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति हुई, निर्मला पति मुकेश द्वारा नौकरी के लिए दिए गए आवेदन और प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ न तो जाति प्रमाण-पत्र पेश किया गया न ही जाति प्रमाण-पत्र नही होने पर अजजा वर्ग की होने के परिपेक्ष्य में कोई शपथ-पत्र लिखित में दिया गया न ही नियुक्ति के सम्बंध में कोई आपत्ति दर्ज करवाई गई, बावजूद महिला के खाते में जाति के दस नम्बर देकर नौकरी के लिए पात्र घोषित कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया।

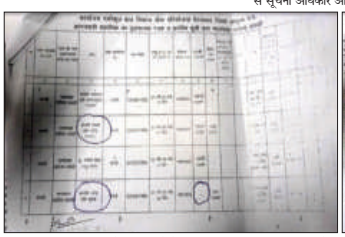

महिला बाल विकास पेटलावद द्वारा जारी तुलनात्मक सूची की प्रमाणित प्रति जिसमे महिला को जाति प्रमाण-पत्र नही होने के कारण नंबर नही दिए गए, महिला सूची में चौथे और आपत्तिकर्ता देवली दूसरे स्थान पर दर्ज है।

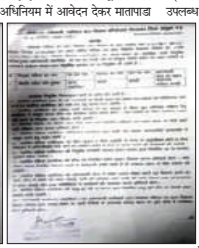

चौथे स्थान पर रही निर्मला पति मुकेश का आँगनवाड़ी सहायिका के पद पर महिला बाल विकास द्वारा जारी नियुक्ति आदेश।

### कलेक्ट्रेट में की गई अपील

नियुक्ति को लेकर आपत्तिकर्ता ने उक्त मामले में जिला कलेक्टर कार्यालय में अपील कर गलत तरीके से महिला की नियुक्ति करने की अपील की है। आपत्तिकर्ता देवली का कहना है कि, एक आवेदन देने के लगभग दो साल बाद कैसे उक्त आवेदन के साथ अलग से कोई दस्तावेज जोड़ कर उसके अंक जोड़े गए,

जबकि महिला द्वारा आवेदन के साथ कोई प्रमाण-पत्र नही दिया, न ही नियुक्ति होने पर और कोई आपत्ति दर्ज करवाई यदि मेरे द्वारा आपत्ति नही ली जाती तो प्रथम स्थान पर बताई गई महिला की नियुक्ति आदेश जारी हो चुका होता, ऐसे में मुझ आपत्तिकर्ता को पाजता आती है, क्योंकि मैं तुलनात्मक सूची में दूसरे स्थान पर रही थी।

जिला परियोजना अधिकारी अजय चौहान से जब इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, समिति का निर्णय है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, उसमें यदि आपत्तिकर्ता द्वारा अपील की गई है तो, हम पिं से मामले को दिखवा लेते।

पेटलावद महिला बाल विकास अधिकारी ने इस विषय मे कहा है कि, आपत्तिकर्ता देवली ही पात्र हैं, लेकिन जिले की जांच समिति द्वारा कैसे चौथे स्थान की महिला को नियुक्ति की गई इसके बारे में वही बताएंगे। पूरे मामले में साफ है दूसरे स्थान पर रही महिला को नौकरी नही मिले इसके लिए षडयंत्र पूर्वक चौथे स्थान पर रही महिला की नियुक्ति की गई। जिम्मेदार अधिकारियों के बयान से स्पष्ट है कि, नियुक्ति के इस फर्जी खेल के पीछे पद, पैसे और राजनीतिक दबाव का उपयोग कर जांच में हेरा-फेरी कर फर्जी रूप से व अपात्र को नियुक्त कर दिया।

# निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2021 का कार्यक्रम जारी

## 16 नवंबर को होगा निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन

**माही की गूंज, बड़वानी।** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2021 का कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अनुसार एक जनवरी, 2021 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियो का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियो में अनुभाग मतदान-केन्द्र के क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करना, मतदान केंद्रों के युक्ति-युक्तकरण की कार्यवाही की जायेगी।

आयोग से प्राप्त जानकारी अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 16 नवम्बर को किया जायेगा। तत्पश्चात 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले व्यक्तियो का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जायेगा। प्रारूप प्रकाशन के बाद से ही 16 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक दावे-आपत्ति प्राप्त किए जायेंगे। अवकाश दिवसो में 21 नवम्बर शनिवार, 22 नवम्बर रविवार, 12 दिसम्बर शनिवार एवं 13 दिसम्बर रविवार को राज्य के प्रत्येक मतदान-केन्द्र पर विशेष कैम्प का आयोजन किया जायेगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 को होगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अरुण कुमार तोमर ने बताया कि, वर्तमान में राज्य में कुल 5 करोड 22 लाख मतदाता हैं, जिनमें 2 करोड 71 लाख पुरुष मतदाता एवं 2 करोड 51 लाख महिला मतदाता हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के 6 लाख 32 हजार 669 मतदाता एवं निःशक्तजन मतदाताओ की संख्या 5 लाख 7 हजार 748 है।

# कब्रिस्तान के सामने शराब दुकान के विरोध में एसडीएम को दिया ज्ञापन

**माही की गूंज, कसरावद।**

कसरावद इंदौर रोड पर कब्रिस्तान के सामने अंग्रेजी शराब दुकान खोलने से मुस्लिम समाज में जबरदस्त आक्रोश है, जिसको लेकर आज अल्पसंख्यक विकास कमेटी जिला अध्यक्ष निजाम बाबा और तहसील अध्यक्ष जाहिद अजमेरी के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वही भीम आर्मी भारत एकता मिशन अध्यक्ष सुनील चौहान तथा भीम आर्मी वरिष्ठ कार्यकर्ता तस्लीम खान ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आवकारी विभाग तथा एसडीएम कसरावद को ज्ञापन सौंपा तत्काल कब्रिस्तान के सामने से शराब दुकान बंद करने का अनुरोध किया।

### कसरावद नगर हमेशा से गंगा-जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है

कब्रिस्तान के सामने यह शराब दुकान मुस्लिम समाज के आक्रोश का कारण बन रही है। कब्रिस्तान मुस्लिम समाज के लिए इबादत की जगह है जहां पर मुस्लिम समाज अपने मरहूम के लिए दुआएं करते हैं, वही शराबियों द्वारा आए दिन उत्पात किया जाता है, शराब की बोतलें कब्रिस्तान के गेट पर फेंक दी जाती है जिसको लेकर मुस्लिम समाज में अपना विरोध दर्ज कराया है, साथ ही इसी रोड पर स्कूल, कॉलेज, जैन मंदिर भी है यदि तत्काल प्रभाव से दुकान को नहीं हटाया गया तो समाज चक्का जाम तथा आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। कसरावद हमेशा से गंगा-जमुनी तहजीब के साथ पहचाना जाता है, यहाँ पर हर समुदाय के लोग मिलकर एवं पुरे सुहार्द पूर्ण तरीके से त्यौहारो को मनाते है।

# सामाजिक न्याय मंत्री ने अन्नपूर्णा अन्न योजना के हितग्राहियों को वितरित किया खाद्यान्न

**माही की गूंज, बड़वानी।**

प्रदेश के पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बुधवार को जिले में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा अन्न योजना के पात्र लोगो को नवीन पात्रता पर्ची एवं खाद्यान्न वितरित किया। इस दौरान उन्होने उपस्थितो को बताया कि, अब पात्रता आ जाने से उन्हें हर माह मात्र 1 रूपए किलो की दर से गेहूँ, चावल एवं नमक तथा प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति सदस्य 5 किलो के मान से खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। इससे हमारे जिले के गरीब लोगो को विशेष लाभ होगा, क्योंकि अब उन्हें बाजार से मंहगा गेहूँ, चावल लेने की आवश्यकता नही पड़ेगी।

बुधवार को शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय बड़वानी के विशाल सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं हितग्राहियों को विशाल एलईडी के माध्यम से भोपाल में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाईव प्रसारण भी दिखाया गया। इस दौरान उपस्थितो को सम्बोधित करते हुए मंत्री श्री पटेल ने बताया कि, योजना के तहत पात्रताधारी लोगो को अब प्रतिमाह उचित मूल्य दुकान से 1 रूपए किलो की दर से यदि राशन मिलने में कोई परेशानी आए तो वे अपने क्षेत्र के जिम्मेदार पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दे, जिससे उन्हें योजना का लाभ लेने में किसी भी स्तर पर परेशानी न आ पाए।

कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि, जिले के सभी पात्र लोगो को यह लाभ मिलेगा, इसके लिए जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानों पर आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उन्होने बताया कि, आज जिले की समस्त 443 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नवीन पात्रताधारी 6999 लोगो को प्रमाण-पत्र एवं पात्रतानुसार राशन वितरित किया जा रहा है।

### गरीबो के लिए जो परेशानी थी वह एक रूपए किलो के राशन से हो जायेगी दूर

श्रीमती तस्लीम शेख को जब अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रदेश के पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने स्टेज पर बुलाकर उन्हें अपने हाथों से पात्रता पर्ची अनुसार 8 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 1 किलो चना, 1 किलो नमक सौपा और घोषणा की कि, अब उन्हें इसी प्रकार खाद्यान्न हर माह 1 रूपए किलो की दर पर नियमित रूप से मिलेगा, तो श्रीमती तस्लीम शेख की आँखे छल-छला आई।

उन्होने स्टेज से ही बताया कि, किस प्रकार वे लॉकडाउन के दौरान परेशान थी, प्रायवेट शिक्षिका होने के कारण उन्हें विगत कई महीनों से आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था। ऐसे में 2 सौ रूपए का राशन लाना भी उनके लिए चुनोतीपूर्ण था, किन्तु अब उन्हें विश्वास हो चला है कि, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना उन जैसे गरीबो के लिए ही बनी है। जिसके माध्यम से वे अब प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न वह भी मात्र 10 रूपए में उचित मूल्य की दुकान से ले आयेंगी। इसके लिए वे मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए खुशी-खुशी बताती है कि, गेहूँ लाने में अब जो राशि बचेगी, उससे वे और उनका पति हरी सब्जी भी खा लिया करेंगे।

# विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

**माही की गूंज, झाबुआ।**

मंगलवार को ग्राम गड़वाड़ा में राष्ट्रीय विधिक स े व ा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के द्वारा ग्राम गडवाड़ा में महिला सशक्तिकरण तथा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीण और जमीन स्तर से जुड़ी हुई महिलाओं ने भाग लिया। सभी महिलाओं को शिविर प्रारंभ होने से पहले प्लास्टिक फेल्डर, राईटिंग पैड, पेन, पर्सनल यूज हेतु पृथक से सेनेटाइजर, मास्क देकर पंजीयन किया गया। सभी महिलाओं को शिविर स्थल पर कोरोना प्रोटोकोल अनुसार लगभग 8-8 फीट की दूरी पर पृथक-पृथक बैठाया गया।

शिविर में महिलाओं को उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी गई तथा विशेष रूप से महिलाओं के लाभ के लिए संचालित शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। महिलाओं को दैनिक जीवन में आने वाली आर्थिक और सामाजिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु, कौशल विकास छोटे घरेलू कुटीर उद्योगों के माध्यम से आर्थिक सम्पन्नता के लिये प्रेरित किया गया। महिलाओं से संबंधित विशेष कानूनों की विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में डिप्टी कलेक्टर ज्योति परस्ते ने शासन की महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। सहायक संचालक महिला बाल विकास वर्षा चौहान द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना तथा वन स्टॉप सेंटर महिलाओं द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में बताया।

# मतदाताओं से दूरी, पूर्व विधायक निर्मला भूरिया के भविष्य की राजनीति पर लगा रहा प्रश्न चिन्ह

## 12 सितम्बर की त्रासदी पर राह ताकती रह गई जनता, पार्टी नेताओं के बीच भी रहा चर्चा का विषय, क्या 2023 में नए चहरे की तलाश में रहेगी भाजपा

**माही की गूंज, पेटलावद।**

भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद स्व. दिलीप सिंह भूरिया की पुत्री पूर्व राज्य स्वास्थ्य मंत्री निर्मला भूरिया अपने आप मे जिले की राजनीति में भाजपा का रबर स्टैम्प नाम है और पिछले 20 से 25 सालों से पेटलावद विधानसभा में भाजपा की राजनीति निर्मला भूरिया के इर्दगिर्द ही घूम रही है, कोई नया चेहरा इस विधानसभा क्रमांक 195 के लिए उभर कर नही आया जो भाजपा समर्थित इस सीट से अपने दम पर जीत दर्ज करने का दावा भर सके, यहाँ से भाजपा के एक बड़ा घड़ा निर्मला भूरिया का नेतृत्व स्वीकार कर निर्मला भूरिया को प्रथम पंगती का नेता मानते है, लेकिन पिता दिलीपसिंह भूरिया के निधन ओर 2018 में विधानसभा चुनाव में मिली मामूली अंतर से मिली हार के बाद निर्मला भूरिया का आम जनता तो ठीक पार्टी के कार्यकर्ता से भी दूरी बनाए हुए है। वही सांसद गुमान की जिले की राजनीति में आमद के बाद से निर्मला भूरिया लगातार हाशिये पर है, गुमान समर्थकों समेत संगठन के द्वारा निर्मला भूरिया की अनदेखी की जा रही है, जिले में तो ठीक खुद के विधानसभा क्षेत्र में होने वाले शिलान्यास, उदघाटन ओर पार्टी के एजेंडे पर होने वाले आयोजनो में से निर्मला भूरिया नदारद है और उसी वजह से उनके समर्थक भी निराश होकर साइलेंट मोड़ पर चले गए, तो कइयों ने गुमान गुट की राह पकड़ ली जिससे लगातार निर्मला भूरिया का जनाधार कम होता जा रहा है, जिसका बड़ा खामियाजा होने वाले संगठन के विस्तार और विधानसभा चुनाव 2023 में निर्मला भूरिया को उठाना पड़ सकता है साथ ही उनके बचे हुए राजनीतिक करियर पर भी ग्रहण लग सकता है।

न किसानों की सूद ली न ही ब्लास्ट पीड़ितों तक पहुँच सकी, राजनीति से दूरी के कयास हुए तेज

12 सितंबर 2015 को पेटलावद में थांदला रोड पर हुए ब्लास्ट में मरे 78 लोगो की पुण्यतिथि शनिवार को थी, पेटलावद भाजपा का ही नही निर्मला भूरिया का भी गढ़ माना जाता रहा है, किसी भी चुनाव में निर्मला भूरिया को यहाँ की जनता ने हमेशा विजय का आशीर्वाद देकर भारी जीत दर्ज करवाई हैं, ऐसे में 12 सितंबर को हुए ब्लास्ट में मरे लोगो की 5वी पुण्यतिथि पर हर कोई आश्वस्त था कि, निर्मला भूरिया इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार का दुख बाटने के लिए कार्यकर्ता के बीच जरूर पहुँचेगी, लेकिन निर्मला भूरिया की अनुपस्थिति ने हर किसी को चौका दिया, नगर भाजपा सहित जिले से कई भाजपा नेताओं ने निर्मला भूरिया की अनुपस्थिति को नोटिस कर उनके स्थानीय समर्थकों से निर्मला भूरिया के नही होने पर सवाल खड़े किये, मेडम की अनुपस्थिति से उनके समर्थकों में भी निराशा देखी गई वही भाजपा में गुटबाजी से गुजर रही निर्मला भूरिया के नही आने पर विपक्षी गुट गुमान समर्थक नेताओ को एक और मौका मिल गया, जो निर्मला भूरिया को राजनीति का रिटायर्ड खिलाड़ी बताने से नही चूक रहे है। पहले से ढलान पर आ चुके निर्मला भूरिया की प्रदेश की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन 2018 में मिली हार से अभी तक नही उभर सकी है।

### किसानों तक भी नही पहुँची

जहां एक ओर निर्मला के पार्टी के ही प्रतिद्वंदी वाहवाही लूटने का कोई अवसर नही गंवा रहे हैं, खुद के विधायक होते जिन

कार्यों को अपनी मेहनत और लगन से आम जनता की सुविधा के लिए स्वीकृत करवाए थे उन कार्यों के शिलान्यास ओर उदघाटन में स्वयं निर्मला भूरिया कही दिखाई नही दे रही है, वही गुमान एंड कम्पनी लगातार अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक के एक काम निपटा कर उन कामो पर सांसद गुमान का टेग लगा रहे हैं, वही किसानों को इस बार हुई असामान्य बारिश में बर्बाद हुई फसल के मामले में भी सांसद गुमान फसल बीमे की घोषणा से लेकर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भोपाल में कृषि मंत्री के साथ फोटो सेशन करवाकर अपने आप को किसान हितेषी बताते हुए वाहवाही लूटते नजर आए, तो दूसरी ओर निर्मला भूरिया अपने विधानसभा क्षेत्र के किसानों से रूबरू तक होने के लिए घर से नही निकली कई क्षेत्रों से निर्मला भूरिया के समर्थकों ने लगातार हर मामले में उनकी उपस्थिति को लेकर अवगत करवाया लेकिन भयंकर निराशा में डूबी एक-दुक्का स्थानों को छोड़कर कही नही दिखी, किसानों की फसल में हुई नुकसानी के मुआवजे के लिए भी कोई आवाज मेडम के गले से नही निकली।

### बड़ी नेता, पर गिरता ग्राफऔर कार्यकर्ताओं से संपर्क की कमी, भविष्य नुकशानदायक होना तय

निर्मला भूरिया पार्टी में केवल अपने पिता की वजह से नही स्वयं भी पार्टी की बड़ी नेताओ में शुमार है, प्रदेश की राजनीति और संगठन में भी उनका अच्छा-खासा दखल है, लेकिन लगातार कार्यकर्ताओ से संपर्क टूटने के कारण उनका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। निर्मला भूरिया के कार्य करने की यही शैली भी रही है, लेकिन दूसरे नेताओं के बढ़ते प्रभाव के बीच मेडम की चुप्पी अब उन्ही के भविष्य के लिए खतरा बनती जा रही है। अंदरूनी सर्वे के अनुसार पार्टी निर्मला भूरिया को एक ओर अवसर देना चाहती हैं, लेकिन इस बार टिकिट उनको तस्तरी में नही मिलने वाली हैं, कई युवा नेता मेडम की राजनीति से दूरी का फायदा उठाने की पेटलावद विधानसभा से दावा करेंगे, वही सांसदी छोड़ कर गुमान भी इसी सीट से विधायक बनने का अपना पुराना सपना सजाये बैठे हैं। परिस्थितियों को देखे तो निर्मला के सामने बड़ी चुनौती टिकिट लेने की नही अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने की होगी।

### स्थानीय संगठन के विस्तार में प्रभाव दिखा कर, कर सकती हैं वापसी, युवा टीम पर दिखाना होगा विश्वास

लगातार हाशिये पर जा चुकि पूर्व विधायक निर्मला भूरिया के पास अपने डूबते करियर को तराने के लिए अंतिम अवसर संगठन में होने वाले विस्तार में अपना प्रभाव दिखाकर कर सकती है, बताया जा रहा है, नए जिलाध्यक्ष के आने बाद 6 माह से जिला संगठन और मण्डल स्तर की सभी कार्यकारणी केवल प्रभाव की लड़ाई में रुका पड़ा है और आने वाली संगठन के विस्तार के परिणाम से भविष्य की राजनीति से थोड़ी बहुत धूल भी साफ हो जाएगी कि, आखिर भविष्य की राजनीति में किसके प्रभाव के भरोसे मैदान में उतरा जाएगा। फिलहाल निर्मला भूरिया का पूरा फोकस वही बताया जा रहा है, पार्टी की नई उम्र की गाइडलाइन के हिसाब से संगठन की पूरी जिम्मेदारी युवा कंधों पर रहेगी ऐसे में राजनीति में निर्मला के पुराने सहयोगियों के साथ-साथ युवाओं को भी विश्वास में लेना और युवा टीम पर भरोसा करना निर्मला भूरिया के लिए जरूरी होगा। वर्तमान में कई युवा नेता निर्मला के पक्ष और संपर्क में भी है जो अब तक गुमान के प्रभाव में न आते हुए भाजपा के बाद मेडम की ही तारणहार मानते हैं, यदि इस बार कोई बड़ी उठा-पटक नही हुई तो जल्द ही संगठन विस्तार के परिणाम आ सकते हैं जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

## कनेरी डेम में नहाने गए युवक की डूबने से मौत, एक दिन बाद मिला शव

**माही की गूंज, रतलाम।**

रतलाम डीडी नगर थाना क्षेत्र कनेरी डेम में रविवार दोपहर डूबे एक 20 वर्षीय युवक का शव सोमवार सुबह डेम के करीब मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौप दिया है। रविवार दोपहर नयापुरा हाल मुकाम शेरानीपुरा निवासी यासीन पिता अब्दुल रशीद खान 20 वर्षीय अपने दोस्तों के साथ कनेरी डेम पर घूमने के लिए गया था। डेम के पास गिरते हुए झरने में सभी लोग नहा रहे है। इसी दौरान यासीन का पैर फिसल गया और डेम के पास गहरे पानी में डुब गया, काफी समय तक उसके बाहर नहीं आने पर घटनास्थल पर मौजूद लोगो ने पुलिस को सुचना दी, पुलिस सुचना मिलते ही रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देर रात तक यासीन की तलाश की लेकिन अंधेरा होने के कारण पुलिस को

सफलता नहीं मिली। सोमवार सुबह पुलिस ने एक बार फिर रेस्क्यू शुरू किया, रेस्क्यू टीम को यासीन का शव गहरे पानी में पत्थरों के बीच फसा हुआ मिला, मृतक यासीन ट्रेलर का कार्य करता था।

## एमपीईबी के बाबू का दुर्व्यवहार, टीआर के नाम पर भी करता है वसूली, जेई ने मांगी माफी

**माही की गूंज, झबुआ।**

हर बिजली उपभोक्ता वर्तमान में आ रहे भारी भरकम बिल से परेशान है। वही अपनी समस्याओं को लेकर अगर खबासा एमपीईबी में बाबू को जाकर समस्या बताई जाती है तो, वह उपभोक्ता के साथ दुर्व्यवहार कर उपभोक्ता को जो मन में आए वो कहकर किसी के सामने भी अपमानित कर देता है और उपभोक्ता अगर बाबू की हरकतों के बाद उसका नाम पूछ ले तो कार्यालयीन कार्य व सरकारी कर्मचारी का रोब झाड़कर उपभोक्ता को पुलिस का डर बताकर कानूनी कार्रवाई करवा देने तक धमकाने में बाबू पीछे नहीं हटता है। ऐसा ही कुछ मामला मंगलवार को भी सामने आया, भामल निवासी जोरावरसिंग पिता उदयसिंग राठौर का घरेलू बिजली बिल 6 हजार 7 सौ 27 रूपए आया, उक्त भारी-भरकम बिल आने के पश्चात उपभोक्ता एमपीईबी कार्यालय में पहुंच कर बाबू संतोष जैन को बताया कि, घर में नाममात्र ही बिजली खर्च होती है और इतना बिल कैसे आ गया? बाबू दुर्व्यवहार के साथ बातें करने लगा, बात बढ़ने पर बाबू ने कहा, 2017-18 में मीटर बंद था, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद कितना बिल आया है, जिस पर उपभोक्ता ने कहा मैं तो प्रति महीने नियमित बिल भरता हूं, तो फिर 2017-18 का ऑडिट अब क्यों? बता दें कि, पिछले माह भी मीटर बंद के नाम से ऑडिट का कह कर कई उपभोक्ताओं को भारी-भरकम बिजली बिल थमाए गए थे। वही बाबू पर उसके दुर्व्यवहार के आरोप के साथ कार्यालय में टीआर रिपोर्ट के नाम पर 8 सो रुपए की मांग की गई का आरोप गूंज के समक्ष गोपाल चौहान ने लगाया।

गोपाल चौहान ने आरोप लगाते हुए गूंज प्रतिनिधि की उपस्थिति में जेई मुकेश परमार को कहा कि, मकान के निर्माण कार्य हेतु उनकी भाभी खेहलता बलराम चौहान के नाम से अस्थाई कनेक्शन हेतु कार्यालय में वे गए तो बाबू ने 4 हजार रुपए मांगे जिसमें 32 सौ रुपए की रसीद देने व की बात के साथ उपभोक्ता ने बाबू का नाम पुछ लिया, तो बाबू ऐसा रोब झाड़ने लगा कि, तू मेरा नाम पूछने वाला कौन होता है, अभी पुलिस को बुलवाकर तेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करवा कर अंदर करवा दूंगा, धमकाने तक पीछे नहीं रहा।

8 सौ रुपए ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट के नाम के लगेंगे। अस्थाई कनेक्शन में किसी प्रकार की टेस्ट रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वही बाबू ने टेस्ट रिपोर्ट के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है ,श्री चौहान ने कहा, अगर मैं कानून की बात नहीं करता तो मुझे 4 हजार की रसीद की बजाय 32 सो रुपए की रसीद देकर बाबू 8 सौ रुपए अपनी जेब में रख लेता।

श्री चौहान ने जेई को यहां तक कहा कि, बाबू का दुर्व्यवहार व आम उपभोक्ताओं के साथ इस प्रकार की अवैध वसूली के साथ उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल भी थमाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली को धूमिल करने का प्रयास एमपीइबी द्वारा किया जा रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद बाबू के दुर्व्यवहार व टीआर के नाम से 8 सौ रुपए कि वो गई मांग को लेकर जेई मुकेश परमार ने गूंज के समक्ष माफी मांगी।

## देपालपुर की घटना को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

**माही की गूंज, पेटलावद।** देपालपुर के चटवाड़ा गांव में दलित महिला के शव को असामाजिक तत्वों द्वारा नहीं जलाए दिए जाने पर अखिल भारतीय बलाई महासंघ, डॉ अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ, संत रविदास मित्र मंडल व भीमराव जन्मोत्सव समिति के द्वारा संयुक्त रूप से राज्यपाल महामहिम एवं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सोमवार को पेटलावद तहसील कार्यालय में दिया, जिस ज्ञापन में देपालपुर की घटना की घोर निंदा करते हुए असामाजिक तत्वो पर तत्काल उचित कार्यवाही करने की मांग रखी व तत्काल चरपोटा गांव में सार्वजनिक मुक्तिधाम निर्माण किए जाने की मांग भी ज्ञापन में रखी गई। मांग पत्र में यह भी कहा गया कि, जल्द ही इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश भर में इस घटना को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन देते समय अखिल भारतीय बलाई महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिसोदिया, डॉ अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश सिसोदिया, रविदास मित्र मंडल के संयोजक पार्षद जगदीश जाटव, भीम जन्मोत्सव समिति के आयोजक मनोज परमार एवं जिला महासचिव विजय मालवीय, बाबुसिंह लिमड़िया, अनिल मालवीय, शंकर मालवीय, रवि मालवीय, पत्रकार सुनील खोडे, पत्रकार ओपी मालवीय, मुन्नालाल खोडे, दीपक धमाण, दीपक सिसोदिया आदि समाजजन उपस्थित थे।

## कपास का पंजीयन 15 अक्टूबर तक होगा

माही की गूंज, झाबुआ। जिले में खरीफ फसल कपास का पंजीयन 15 सितम्बर से प्रारम्भ होकर 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास एनएस रावत ने जिले के किसानो से अपील की है कि वे अपने नजदीकी पंजीयन केन्द्र पर ई-उपार्जन पोर्टल पर खरीफ2020 में कपास फसल का पंजीयन करवाकर शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लें। किसान अपना पंजीयन निरूशुल्क करवा सकते हैं। पंजीयन के लिए चयनित फसल कपास, धान, ज्वार, बाजरा है। यदि पंजीयन केन्द्रों पर अधिक संख्या में कृषक एक साथ उपस्थित हो रहे हो तो कोविड-19 की गाईड लाईन का कड़ाई से पालन करते हुए पंजीयन उसी समय में नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित कृषक पंजीयन केन्द्र से टोकन प्राप्त कर निर्धारित समय पर पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन के लिए कृषकों को खसरा अथवा वन अधिकार पट्टे इत्यादि में से कोई एक दस्तावेज साथ की स्व प्रमाणित छाया प्रति की आवश्यकता होगी। यदि कोई कृषक अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक पंजीयन नहीं करवा सकेंगे तो शासन की उपार्जन व अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगें।

## अवैध और अविकसित कॉलोनियां काटकर जनता के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में एफआईआर दर्ज

### पूर्व नपाध्यक्ष व दो अन्य भाजपा-भाजयुमो नेताओं के साथ कुल 8 कॉलोनाइजरों के नाम एफआईआर में शामिल

**माही की गूंज ,रतलाम।**

कलेक्टर गोपालचंद्र डाड के निर्देश पर जिले में अवैध कालोनियों के कालोनाइजरों के विरुद्ध शिकंजा कसा जा रहा है। इस सम्बन्ध में रतलाम जिले के जावरा में 10 कालोनाइजरों के विरुद्ध कार्यवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

एसडीएम राहुल धोटे ने बताया कि, 12 सितम्बर को जावरा पुलिस थाने पर 10 एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें एक एफआईआर जावरा शहर थाना एवं 9 एफआईआर औद्योगिक क्षेत्र थाने में दर्ज कराई गई। जावरा शहर में कुल 142 कालोनियों का निर्माण किया गया है जिनमें से 33 कालोनिया ही हस्तांतरित की गई है। शेष 39 कालोनी अविकसित होने से अहस्तांतरणीय हैं, शेष 70 कालोनियां पूर्णतः अवैध की श्रेणी में रखी गई है, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य पर भी कार्रवाई जारी है। वर्तमान में एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही मानव अधिकार आयोग द्वारा प्राप्त उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में की गई है जो आयोग को तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा शिकायत में आयोग को भेजी गई थी। मानव अधिकार आयोग को की गई उस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आयोग द्वारा प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन भोपाल, आयुक्त उज्जैन संभाग, कलेक्टर जिला रतलाम को पत्र जारी कर जांच करवाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।

### दल बनाकर की गई जाँच

एसडीएम द्वारा दल गठित कर अवैध एवं अविकसित कालोनियों की जांच कराई गई। जांच में जिन कालोनियों में कमियां पाई गई उनके विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन कालोनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उनमें सत्य साई विहार कालोनी, तिलक विहार कालोनी, पहाड़िया रोड स्थित अरिहंत कालोनी के पास स्थित कालोनी के कालोनाइजर राहुल पिता चन्द्रप्रकाश ओस्तवाल, आदर्श नगर कालोनी कालोनाइजर प्रकाशचन्द्र पिता पारसमल, राजेन्द्र जयन्त परिसर कालोनाइजर अनिल कुमार एवं विजय कुमार पिता मोतीलाल दसेडा, मंदसौर रोड जावरा स्थित कालोनी कालोनाइजर मोहम्मद आसीफ मिर्जा पिता अब्दुल गफ्फर मिर्जा, जैन कालोनी कालोनाइजर अनिल कुमार पिता प्रकाशचन्द्र कोठारी, संजय काम्प्लेक्स कालोनी, तथा ग्राम सेजावता में निर्मित दो संजय काम्प्लेक्स के संजय पिता हीरालाल गंगवाल शामिल हैं।

उपरोक्त कालोनियों की जांच दल द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मानव अधिकार आयोग रजिस्ट्रार (लॉ) भोपाल के निर्देशानुसार सक्षम अधिकारी एवं कलेक्टर जिला रतलाम को कार्यवाही की अनुमति हेतु प्रशासक नगर पालिक परिषद् जावरा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही की अनुमति चाही गई, जिसमें कलेक्टर द्वारा संबंधित कालोनियों के कालोनाइजरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश 5 सितम्बर को दिए गए, जिसके पालन में प्रशासक नगर पालिका परिषद् द्वारा 10 सितम्बर को मुख्य नगर पालिका अधिकारी जावरा को प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आदेश किया गया था जिसके उपरान्त संबंधित कालोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई।

## और कितने अपनो का जीवन छिनेगा कोरोना? अपनो के अंतिम दर्शन को तरसे अपने

### राजेंद्र कासवा की पत्नी व पत्रकार अर्पण कासवा की माताजी अंगूरबाला कासवा का निधन

**माही की गूंज, बामनिया।**

सोशल मीडिया पर कोरोना काल के चलते एक हकीकत बात वाइरल हो रही है कि, मौत का भी समय बदल गया...ना गंगाजल, ना किसी के कंधे का सहारा, ना कोई विश्राम, ना राम-राम बस सीधा पैकिंग और शमशान यानि अब अपने अपनों के ही अंतिम दर्शन के लिए तरसे है, शायद न हीं ऐसा काल कभी आया होगा न कभी आए।

कोरोना का कहर और कितनो का जीवन छिन लेगा ? पता नही, शनिवार को बामनिया में शोक स्तब्ध कर देने वाली खबर आई, अनाज के दलाल राजेन्द्र कासवा की पत्नी और बारदान व्यापारी पत्रकार अर्पण कासवा की माता श्री अंगूरबाला कासवा का दुःखद निधन हो गया, पत्रकार साथी अर्पण कासवा का परिवार विगत दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया था, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर अंगूरबाला कासवा को इलाज के लिए इंदौर भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उनकी मृत्यु की खबर ने नगरवासियो को झकझोर कर रख दिया। फिलहाल परिवार रतलाम में निवासरत है लेकिन व्यापार के माध्यम से परिवार बामनिया से जुड़ा हुआ है और बड़े तीज-त्यौहार परिवार बामनिया में ही मानता है। हसमुख ओर मिलनसार अंगूरबाला कासवा जब भी बामनिया आती थी, सभी से बड़ी आत्मीयता से मिलते थे। कासवा परिवार में हुई बड़ी क्षति से नगर और पत्रकार जगत में शोक व्याप्त है, जिला पत्रकार संघ की और जिला अध्यक्ष संजय भेटवा, व्यापारी संघ बामनिया की और से रामेश्वर गर्ग, पत्रकार संघ बामनिया की से नगर अध्यक्ष सत्यनारायण गोंड, माँ अम्बिका सेवा समिति के मोहन अग्रवाल, राजेश सोनी, जैन समाज की और भंवरलाल बाफना, स्थानीय भाजपा इकाई की और से भाजपा नेता अजय जैन, ग्राम पंचायत बामनिया की और से सरपंच रामकन्या मखोड़, उपसरपंच लोकेंद्र कटकानी आदि ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए कासवा परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है।

### गूंज अपील

कोरोना कोविड-19 संक्रमण को लेकर जागरूक और सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करे मास्क,सेनेटाइजर का उपयोग करे, सर्दी, खासी या बुखार या शंका होने पर डॉक्टर को दिखाए ओर जाँच करवाए। जरूरी होने पर ही घर से निकले भीड़-भाड़ में जाने से बचे, बीमारी बताने से नही छुपाने से बढ़ती हैं। ध्यान रखे सुरक्षित रहे।

## ड्यूटी से लौट रहे हेडकांस्टेबल की दुर्घटना में हुई मौत

**माही की गूंज, रतलाम।** शहर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को ड्यूटी से लौट रहे एक हेड कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रावटी थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल रामप्रकाश पिता रामरतन जाटव (59) थाने से अपना काम कर बाईक से घर लौट रहे थे कि, उमरगांव एवं मोरिया के बीच रास्ते में भैंस आने से संतुलन बिगड़ने से बाईक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे हेड कॉन्स्टेबल बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने रामप्रकाश को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान करीब साढे 8 बजे मौत हो गई।

## सुप्रीम कोर्ट से बोली सरकार- सांसदों, विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामले तेजी से निपटाए जाएं



**नई दिल्ली, एजेंसी।** केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पूर्व और वर्तमान सांसदों व विधायकों के खिलाफलंबित आपराधिक मुकदमों को तेजी से निपटाने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि, इन मामलों को एक निश्चित समय-सीमा में उनके नतीजों तक पहुंचाना जरूरी है। न्यायमूर्ति एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, इन मामलों के तेजी से निस्तारण के बारे में न्याय-मित्र विजय हंसारिया के सुझावों पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मेहता ने कहा कि, अगर विधि निर्माताओं के खिलाफ लंबित मामलों में उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगाई है तो, शीर्ष अदालत को उसे ऐसे मामले में निश्चित समय-सीमा के भीतर निर्णय करने का निर्देश देना चाहिए।

मेहता ने कहा, शीर्ष अदालत जो भी निर्देश देगी, भारत सरकार उसका स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि, यदि विशेष अदालतों में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कोई मसला है तो शीर्ष अदालत संबंधित राज्य सरकार को ऐसे मामले में ज्यादा से ज्यादा एक महीने में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे सकती है।

# घर के आगे से नहीं हटाया तो करेंगे सरकारी भवन के आगे अतिक्रमण

### निजी भूमि और घर के आगे के अतिक्रमण को हटाने की लगाई गुहार, राजस्व और पंचायत एक दूसरे को जिम्मेदार बताकर टाल रहे मामला

**माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत**

राजस्व न्यायालय मतलब जिसकी लाठी उसकी भेस की कहावत को चरितार्थ कर रही है, जिससे अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले राजस्व के जिम्मेदार लोगों की भेंट-पूजा कर लाखो करोड़ो की जमीनो पर अतिक्रमण कर हतियाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओ ने राजस्व के अधिकारियों की कमजोरी का फायदा उठाकर लोगो की निजी भूमि के आगे भी अतिक्रमण कर लिया और खुद की भूमि के आगे से अतिक्रमण हटाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, कई बार राजस्व के अधिकारियों और ग्राम पंचायत से गुहार लगाने के बाद भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर राजस्व ओर पंचायत एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यहाँ अतिक्रमणकर्ताओ से बड़ी कीमत वसूलकर उनको न केवल सरक्षंण दे रहे हैं बल्कि बढ़ावा भी देकर अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय भूमि बेचकर अपनी जेब भर रहे हैं।

#### अतिक्रमणकर्ताओं से वसूली कर दबाया जा रहा हैं मामला

पेटलावद राजस्व विभाग के अंतर्गत ग्राम बनी में कई लोगो ने निजी भुमी के आगे रोड से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध गुमटियां लगा ली, लेकिन न पंचायत ने न ही राजस्व विभाग ने सुद ली, जिससे प्रोतसाहित अतिक्रमणकर्ताओ ने कुछ लोगो के घर के आगे भी अतिक्रमण कर आने-जाने का मार्ग ही बन्द कर दिया, किसी की निजी भूमि आगे पड़ी शासकीय भूमि पर कतई उस भूमि स्वामी का अधिकार नही होता है, लेकिन इस प्रकार की भूमि का उपयोग निजी भूमि पर आवाजाही के लिए करते है। ग्राम बनी में ऐसे एक नही तीन मामले सामने आए हैं, जहां घर के आगे बढ़ते अतिक्रमण से परेशान शंभुदास बैरागी, नानू पिता भेरू मुनिया और कालू मचार तीनो निवासी बनी ने अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद को अतिक्रमण को हटाने के लिए आवेंदन दिया है, फिलहाल अनुविभागीय अधिकारी ने मामले की जाँच राजस्व निरिक्षक मचार को दी, लेकिन मामले में पहले भी शिकायत हो चुकी है, जिसे ऊपर-ऊपर ही निपटा दिया गया था।

ननु मुनिया जिसके घर के आगे आशा कार्यकर्ता ने कब्जा कर ननु की निजी भूमि पर बने मकान की आवाजाही बन्द कर दी।



कालू मचार के घर के आगे लम्बा चोडा अतिक्रमण कर अवैध गुमटी ओर उखेड़ा बना कर घर की आवाजाहि पूरी तरह से बन्द कर दी मजबूरन दुकान लेकर कालू को भी सड़क पर आना पड़ा।



शंभुदास बैरागी के घर के आगे रखी हुई अवैध गुमटी और ढालिया जिससे बैरागी परिवार की आवाजाही बाधित हो रही है।

शिकायतकर्ताओ का कहना है कि, राजस्व विभाग के जिम्मेदार अतिक्रमणकर्ताओ को लेंन-देंन कर बचा रहे हैं, जिससे हम लोगो को हमारी निजी भूमि पर बने घरो में आने-जाने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही और उल्टा अतिक्रमणकर्ता अपने अतिक्रमण को लगातार बढ़ाता जा रहा जिसकी कोई सूद नही ले रहा।

#### शासकीय भवनों के आगे अब करेगे अतिक्रमण

मामले में शिकायतकर्ताओ ने परेशान होकर न्याय नही मिलने की स्थिति में खुद अतिक्रमण करने का रास्ता तय किया है। शिकायतकर्ता शंभुदास, ननु और कालू ने बताया कि, यदि निजी आवास के आगे किये गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासन नही हटाता है तो हम भी उसी अतिक्रमण प्रक्रिया के साथ पहले गाव में बने शासकीय भवनों के आगे पड़ी खाली भूमि सहित गाव की दूसरी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर तहसील परिसर में खाली पड़ी भूमि पर भी अतिक्रमण करेंगे। मामले में जाँच करने वाले राजस्व निरीक्षक ने जाँच शुरू करने से पहले ही मामले से पल्ला झाड़ने की बाते करना शुरू कर दी। राजस्व निरिक्षक का कहना है कि, मामला आबादी भूमि से जुड़ा है जिसका निराकरण पंचायत को ही करना है, हम सिर्फ जाँच रिपोर्ट बनाकर दे देंगे।



शिकायतकर्ता ननु, शंभुदास ओर कालू आवेदन के साथ।

वही ग्राम पंचायत बनी के सचिव का कहना है कि, हम तो अतिक्रमण हटाने को तैयार है पर राजस्व के अधिकारी आकर कार्यवाही करे।

पुर्व में हुई शिकायत की जांच में पंचनामा बनाकर अतिक्रमण बताने वाली हल्का पटवारी से मामले में चर्चा करने का प्रयास किया, लेकिन पटवारी ने फोन रिसीव नही किया।

#### उम्मीद है न्याय मिलेगा

शिकायतकर्ता शंभुदास बैरागी जो 70 वर्षीय बुजुर्ग होकर खुद पंचायत सचिव के पद से रिटायर्ड हुए है उनका कहना है कि, अनुविभागीय अधिकारी आईएएस है और हमारी बात को पूरा सुना है, उम्मीद हैं हमारी शिकायत पर कार्यवाही करेंगे। शंभुदास का कहना है कभी सोचा नही था उम्र के इस पड़ाव पर आकर जायज काम करवाने के लिए न्यायलय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अन्य शिकायतकर्ता ननु मुनिया का कहना है कि, मेरे घर के आगे मेरी निजी भूमि सहित शासकीय भूमि पर शासकीय कर्मचारी आशा कार्यकर्ता द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा जो राजस्व के अधिकारियों की उपस्थिति में भी विबाद करने पर उतारू होकर राजस्व के अधिकारियों को अतिक्रमण नही हटाने की खुली चुनोती देती है, फिर भी राजस्व अमले द्वारा अतिक्रमण नही हटाया जाता है। एक और शिकायतकर्ता कालू मचार ने कहा कि, स्वयं के मकान के आगे अतिक्रमणकर्ता ने कब्जा कर लिया है जिसके चलते रोजगार के लिए मुझे भी सड़क पर आना पड़ा, अगर घर के सामने से अतिक्रमण हटता हैं तो मैं अपना रोजगार घर मे कर सकता हु।

## बिना बर्तन लाए ही फर्जी बिल के साथ भ्रष्टों ने निकाल ली राशि

### दुसरे फर्जी बिल से भी निकाले 43 हजार

**माही की गूंज, खच्चरटोड़ी। विकास साबलिया**

मेघनगर जनपद की ग्राम पंचायत खच्चरटोडी में सचिव किशोर कटारा व सरपंच ने मिलकर किए गये भ्रष्टाचार के खेल अब परत दर परत खुल रहे है। पंचायत मे एक ओर भ्रष्टाचार पकड मे आया है। दरअसल शासन ने पंचायतों को गांव में सामुहिक रुप से बर्तन देने के लिये पंचायत की राशि से बर्तन खरीदने के निर्देश दिए। लेकिन खच्चरटोडी पंचायत में ये बर्तन सिर्फकागजो मे ही पहुचें है।

भ्रष्टाचार करने में माहिर एंव ग्रामीणों को झुठ बोल कर गुमराह करने वाले सचिव किशोर कटारा ने प्रीति ग्रह भण्डार थान्दला के मालिक से मिलीभगत कर इसी दुकान से बर्तन खरीदी बताकर 75 हजार का फर्जी बिल लगाकर पेसे निकाल लिए। जब सचिव कटारा से सवाल किया गया तो, सचिव महोदय अंहकार भरे स्वर मे बोले की बर्तन ले आए है ओर पंचायत के तीनो गांव मे बाट दिए है। लेकिन जब प्रीति ग्रह भण्डार के मालिक से बात की गई तो वे दबी आवाज मे बोले की अभी बर्तन नही ले गए है ओर उनकी दबी आवाज ने ही भ्रष्ट पंचायत के नुमाईदो के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। सचिव किशोर कटारा ओर प्रीति ग्रह भण्डार के मालिक के विरोधाभास कथन से सचिव महोदय के कारनामे पुरी तरह से साफहो गए। आपको बता दे कि, ये वही सचिव है जिन्होने पंचायत मे हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवक को डराने-धमकाने के लिए चोकी रम्भापुर में एफआई.आर. दर्ज कराने का एक आवेदन टाईप कराकर धमकाया था की हमारा भ्रष्टाचार उजागर करेगा तो झुठे केस में फसाकर जेल भिजवा देगे।

#### सचिव ने आते ही कर दिया था 43 हजार का भ्रष्टाचार

सचिव मार्च माह नें खच्चरटोडी पंचायत में आए थे, 1 महिने के भीतर ही सचिव ने सरपंच के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की दुकान शुरू करते हुए नाली क्रोसिंग निर्माण के नाम पर 60 बैग सीमेंट, तीन-तीन ट्राली रेत-गिट्टी खरीदी बताकर 43 हजार का फर्जी बिल लगाकर राशि निकाल ली थी। इसके अलावा सरपंच-सचिव ने गणतंत्र दिवस पर बच्चो को बंटने वाली लुग्दी को भी नही छोडा।



#### सरपंच के चहेते है सचिव

ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचारी सचिव को हटाने के लिये आवेदन भी दिया है। लेकिन सरपंच नही चाहते की उनके चहेता सचिव यहा से हटे, ताकी भ्रष्टाचार की दुकान बंद न हो। ग्रामीणों का कहना है कि, सरपंच निजि स्वार्थ में इतने अन्धे हो गये की वे भूल चुके है की वे 5 साल के लिये चुने जाने जनप्रतिनिधि है। पंचायत कार्यालय खुल रहा है या नही, ग्रामीणों का काम हो रहा है या नही, इससे सरपंच महोदय को कोई मतलब नही। ग्रामीणों के समर्थन में न आकर सचिव के साथ रहना आगामी पंचायत चुनाव में सरपंच को मंहगा पड सकता है। हम जनता है साहब, कुर्सी पर तीन तिहाई वोटो से बिठा सकते है तो कुर्सी से हटा भी सकते है।

## प्रशासन पस्त, गांव-गांव चल रही हैं अवैध मयखाने

**माही की गूंज रतलाम, राघवेन्द्र सिंह डोडिया**

रतलाम जिले में नशा कारोबारियों के इरादे इस कदर बुलंद है कि समूची छोटे से देहातों से लेकर बड़े कस्बों तक में खुलेआम अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। अवैध शराब बिक्री का मामला जिले में चरम पर है। शराब माफिया धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करता नजर आ रहा है, लेकिन तथाकथित समाज एवं लॉ इन आर्डर के रक्षक कहे जाने वाला महकमा गैर कानूनी कार्यो पर लगाम लगाने के बजाय खुलकर माफियाओं का समर्थन करता नजर आता है। समूचे क्षेत्र में युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहा है, जिसका मुख्य कारण अवैध रूप से शराब का सरलता से उपलब्ध होना है। शराब के आसानी से उपलब्ध होने के कारण स्कूलों में पढने वाले युवा छात्र भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। जानकारों की मानें तो अव्यस्कों से शराब मंगाना या उन्हें शराब बेचना अपराध की श्रेणी में आता है, बावजूद इसके शराब माफियाओं को इस बात का कोई डर नहीं है, उन्हें सिर्फपैसे कमाने से मतलब रहता है।

#### एसपी गौरव तिवारी की अवैध शराब माफिया पर कार्यवाही ढीली

आबकारी विभाग तो शुरू से वैध अवैध शराब के व्यापार को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार अवैध शराब के विक्रय पर लगाम लगाने के लिए जुटी रहती है, रतलाम जिले का भार संभालते ही पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने शराब माफियाओं की नाक में दम कर दिया था, लेकिन धीरे-धीरे पुलिस की पकड़ इस काले कारोबार पर अब ढीली हो गई है और आबकारी विभाग के साथ-साथ पुलिस की भूमिका पर भी उगली पुलिस की कार्यप्रणली को लेकर उठ रही हैं। गौरतलब है कि, सम्पूर्ण क्षेत्र में शराब माफियाओं एवं आबकारी विभाग की जुगलबंदी की चर्चा हर जुबान पर है। आपको बता दें कि, सैकड़ा भर गांवों में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस एवं आबकारी विभाग को भी है, बाबजूद कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे प्रतिदिन लड़ाई-झगड़े होते हैं एवं अपराधो को भी अंजाम दे रहे है, पुलिस की मिलीभगत के कारणे अवैध शराब विक्रेताओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। विश्वनीय सूत्रों की माने तो गावों में सरेआम शराब की बिक्री घरों, सेअंडों के ठेले, और ढाबो से हो रही है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में यह नशे का कारोबार जमकर करवाया जा रहा है, जिसका सीधा असर ग्रामीणों की जीवनशैली पर पड़ रहा है। अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए बनाया गया आबकारी अमला कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, महज औपचारिकता निभाने के लिए कभी कभार थोड़ी बहुत शराब जप्त कर अपनी खानापूर्ति कर वाहवाही लूटी जाती है। जबकि उक्त विभाग का काम सिर्फअवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाना है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा की जा रही अनदेखी की कीमत क्षेत्र के लोग चुकाने को मजबूर हैं। मामले में जब पुलिस से अवैध शराब विक्रय के बारे में बात की जाती हैं तो, जान के अंजान बनी पुलिस पत्रकार को अवैध शराब की जानकारी देने और कार्यवाही करने की बात कह कर पल्ला झाड़ लेती हैं।



# चोरों ने की चोरी कबूल, पर पुलिस ने अवैध शराब का किया मामला दर्ज

### चोरी के आरोप में चोर कुछ दिन तो, शराब के मामले में रहता है कई महीनों जेल

**माही की गूंज, खवासा।**

वैसे तो पुलिस को यह कतई अधिकार नहीं है कि, कोई व्यक्ति अपराध क्या करें और उस पर मामला कुछ ओर दर्ज कर दे। मध्यप्रदेश में आबकारी अधिनियम 2000 के तहत धारा 34(2) में मामला दर्ज होने पर कई महीनों की जेल की हवा खानी पड़ती है, वही चोरी जैसे अपराध में चोर चोरी को अंजाम देकर 2 से 4 दिन में ही कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर आ जाते हैं और अपराधी फिर से चोरी जैसे अपराध को अंजाम देते हैं। जैसे अवैध शराब की रोकथाम के लिए 50 लीटर से ऊपर शराब मिलने पर कानून को सख्त करते हुए उसकी जमानत प्रक्रिया को जटिल कर जमानत पर रोक लगाई है, उसी तरह अगर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए भी सरकार को चोरी का मामला दर्ज होने के बाद जमानत को जटिल प्रक्रिया बनाने का प्रावधान संसद में पास करना आवश्यक है, ताकी चोरी जैसे अपराध में कमी आ सके।

वैसे तो जिले में कई चोरियों के मामले पुलिस अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए अपराध दर्ज ही नहीं करती है, इतना ही नहीं यहां तक भी देखा गया है कि, चोरी जैसी घटना में शिकायत करने वाला का आवेदन तक पुलिस नहीं लेती है। वही जब किसी के यहां चोरी होती है तो फरियादी द्वारा ही अपने बल-बूते व अपने सूचना तंत्र पर चोर व चोरी गए सामान का खुलासा कर पुलिस को अवगत करवाता है, जिसमे ऐसे कई मामले भी देखे गए हैं कि, चोरों से परेशान होकर पुलिस चोरी गया माल जप्त करती है और चोर चोरी कबूल भी कर लेते हैं पर पुलिस यह अच्छी तरह से जानती है कि, चोरी के मामले में यह चोर दो-चार या 8 दिन में ही बाहर आ जाएंगे और फिर चोरी को अंजाम देकर पुलिस का सर दर्द बनेंगे, खासकर चोरी की घटना बारिश शुरू होने के साथ ही रबी की फसल कटने तक खेतों में पड़े कृषि यंत्र के साथ कई घरों के ताले तोडकर चोरी को अंजाम देते हैं, तो कुछ के खुलासे होने पर चोरी का मामला दर्ज नहीं कर उस पर अवैध शराब जप्ती का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज देते है।

चुकी पुलिस ये जानती है कि, आबकारी अधिनियम के तहत धारा 34(2) में चोरी करने वाला यह आरोपी कम से कम इतने दिन जेल में जरूर रहेंगे जब तक फसलें कटकर बाहर नहीं आ जाए और इतने दिन अंदर रहने के बाद चोरी जैसे अपराध को भी अंजाम नहीं देने की मंशा के साथ पुलिस चोरी जैसी घटना को अंजाम देने पर अवैध शराब का मामला दर्ज कर जेल भेज देती है कि बात कई बार चर्चाओं में रही है। ऐसा ही एक मामला खवासा चौकी अंतर्गत ग्राम नारेला में देखने को मिला, जिसकी शिकायत भी चोरों की पत्नियों ने एसपी कार्यालय में की है।



चोरो की पत्नीयो ने जनसुनवाई में एसपी को शिकायत कर पुलिस की कारस्तानी को किया उजागर।

#### यह है पूरा मामला

दरियावर सिंह माल की पानी की मोटर 29 जुलाई को चोरी हो गई, जिसकी खवासा पुलिस ने न कोई शिकायत ली न कोई एफआईआर दर्ज की। परंतु दरियावर सिंह माल ने अपनी चोरी गई मोटर व चोरो को खोज निकाला, जिसके बाद उसकी मोटर को चोरी करने वाले चोर के नाम व चोरी गई मोटर कहां है की पूरी जानकारी खवासा पुलिस को दी। पुलिस नारेला पहुंची और तेजुड़ी पति कालू वसुनिया के खेत के कुएं में से चोरी गई मोटर व मोटर को चोरी करने वाले चोर कालू वसुनिया, मुकेश गरवाल व दलसिंग निवासी नरेला को पुलिस खवासा चौकी पर 5 अगस्त को लाई, लेकिन यह चोर पुलिस के सर दर्द होने के कारण जिले में पुलिस की चल रही कार्यवाही की परीपाटी के अनुसार चोरी का मामला दर्ज नहीं कर चोरों पर कच्ची शराब जप्त कर उन पर अवैध शराब विक्रय का मामला दर्ज कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत फरियादी के रिश्तेदार दुलेसिंग माल व रमेश वसुनिया को साक्षी बनाकर मामला दर्ज कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

शराब मामले के 40 दिन बाद भी आरोपी की जमानत नहीं होने के कारण आरोपियों की पत्नी तेजुड़ी बाई पति कालू वसुनिया, सुनीता पति मुकेश गरवाल व भूरी पति दलसिंह गरवाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली को उजागर करते हुए मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत कर एसपी को बताया कि, गांव के चौकीदार की उपस्थिति में पुलिस ने दरियावर सिंह की चोरी गई मोटर को जप्त किया व हमारे तीनों के पतियों ने चोरी भी कबूल कर ली, बावजूद उन पर अवैध शराब जैसा झूठा मामला दर्ज किया, जब साक्षीगणों से जानना चाहा की, चोरी की जगह शराब का मामला कैसे दर्ज कर लिया, तो महिलाओं के साथ साक्षीगण एवं उनके 6 रिश्तेदारों ने उनके साथ विवाद करने के संबंध में कार्यवाही हेतु शिकायत दर्ज की गई।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422